

## CURRENT AFFAIRS QUIZ

**Q.1)** निम्नलिखित में से कौन सा निकाय समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत स्थापित है?

1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (International Seabed Authority- ISA)
2. सागरीय कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS)
3. महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग (CLCS)
4. स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration -PCA)

सही कूट चुनें

- a) केवल 1 और 2
- b) 1, 2 और 3
- c) 1, 2 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

**Q.1) Solution (b)**

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत स्थापित निकायों में शामिल हैं -

1. अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA)
2. सागरीय कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS)
3. महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग (CLCS)

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration -PCA) नीदरलैंड के हेग में स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। यह पारंपरिक अर्थों में एक न्यायालय नहीं है, बल्कि सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पक्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौतों से उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं प्रदान करता है।

संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है, लेकिन पीसीए एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है।

**Source:**

1. <https://www.un.org/Depts/los/Links/Links-LOS.htm>
2. <https://www.thehindu.com/news/national/italian-marines-case-india-loses-jurisdiction/article31973247.ece>

**Q.2)** "समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)" के अनुसार

1. प्रादेशिक जल (Territorial waters) 12 समुद्री मील तक होता है।
2. सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone) तट से 200 नॉटिकल मील तक होता है।
3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone): सीमा शुल्क, कराधान, आब्रजन और प्रदूषण: तटीय राष्ट्र चार क्षेत्रों में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

- a) केवल 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 2
- d) इनमें से कोई भी नहीं

**Q.2) Solution (b)**

सन्निहित क्षेत्र (contiguous zone) तट से 24 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। एक सन्निहित क्षेत्र में तटीय राष्ट्र चार क्षेत्रों में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं: जो सीमा शुल्क, कराधान, आब्रजन और प्रदूषण हैं।

# IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

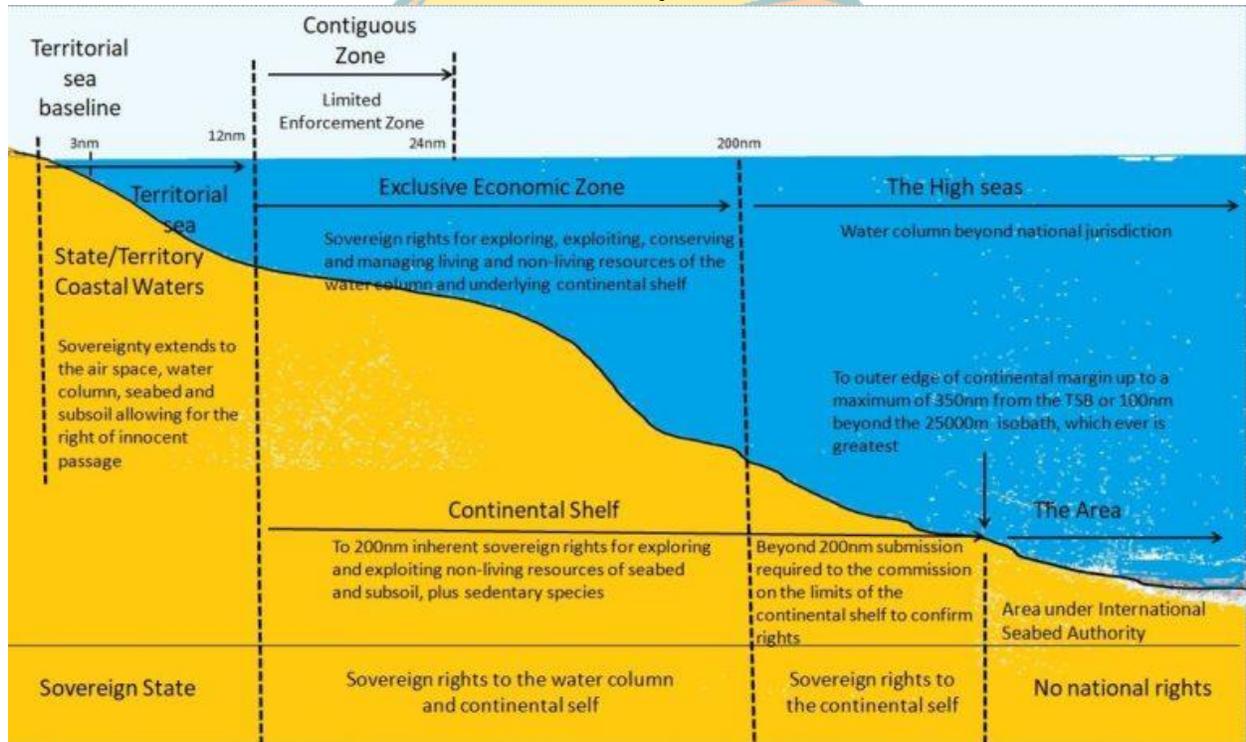
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में, जो 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तटीय देशों के पास संसाधनों का दोहन करने का विशेष अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय जलयान बिना किसी प्रतिबंध के इन जल को पार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं

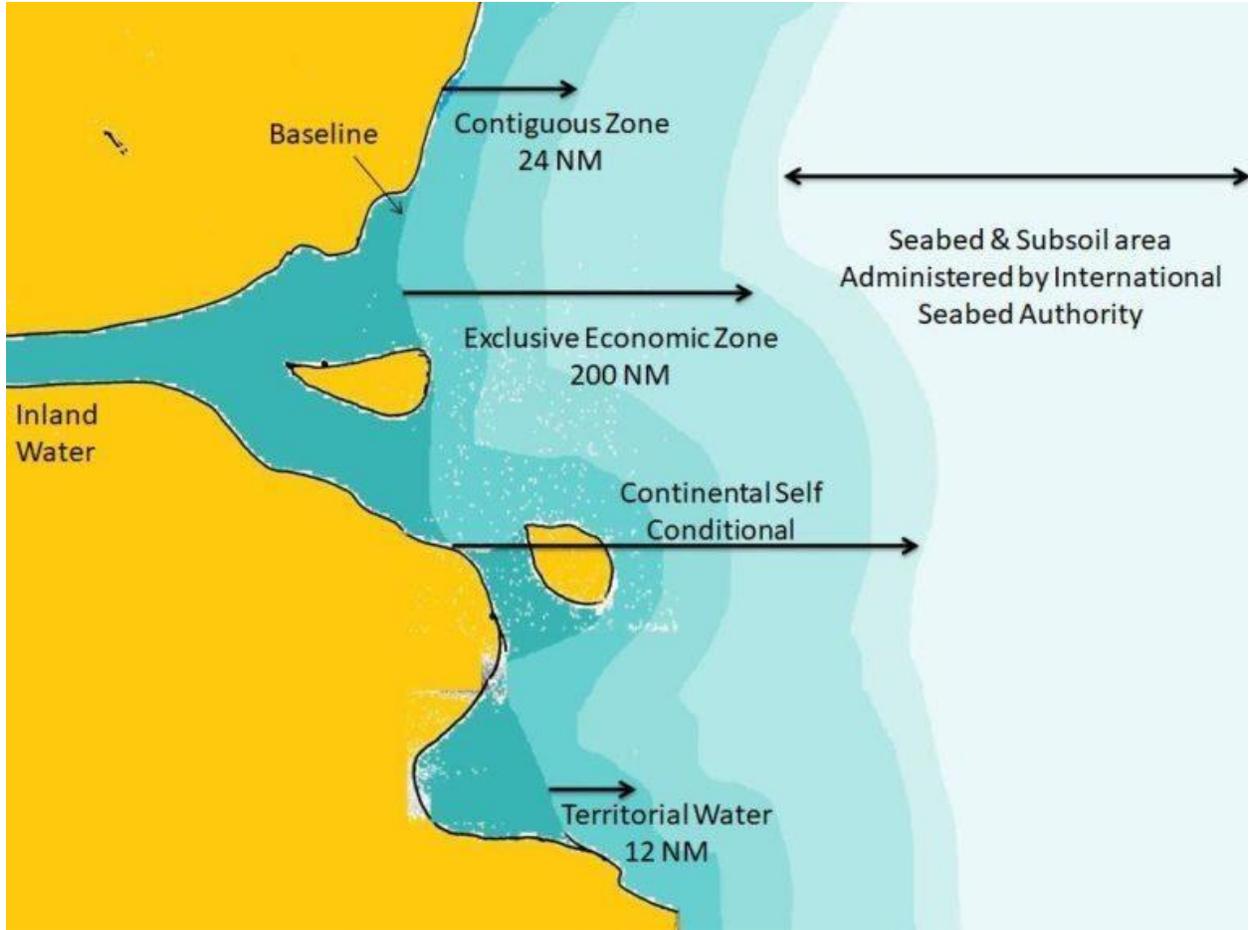
## अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive economic zone)

तटीय राष्ट्र का मछली पकड़ने, खनन, तेल की खोज और उन संसाधनों के किसी भी प्रदूषण सहित अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है। हालाँकि, यह समुद्र की सतह के ऊपर, या समुद्र की सतह के नीचे पारगमन पर रोक नहीं लगा सकता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार, इसके अनन्य आर्थिक हिस्से के भीतर तटीय राज्य द्वारा अपनाए गए कानूनों और नियमों के अनुपालन में है।

## महाद्वीपीय शेल्फ (Continental shelf)

तटीय राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन का अधिकार है, हालांकि अन्य राज्य केबल और पाइपलाइन बिछा सकते हैं यदि वे तटीय राज्य द्वारा अधिकृत हैं। किसी देश के महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमा आधार रेखा के 350 समुद्री मील से अधिक नहीं आगे बढ़ेगी।





**Q.3)** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है
2. प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है
3. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 2
- d) 1, 2 और 3

**Q.3) Solution (d)**

**राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority)**

- एनटीसीए पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को सक्षम करने के तहत गठित है, इसे 2006 में संशोधित करके, बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए, शक्तियों और कार्यों को सौंपा गया है।
- प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जाता है।
- टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत घोषित किए जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आते हैं।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/uttar-pradesh-mulling-over-proposal-to-turn-shivalik-forest-into-tiger-reserve/article31968322.ece>

**Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. जब देश का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) बढ़ता है; इसका व्यापार घाटा (trade deficit) भी बढ़ जाता है।
2. चालू खाता (Current Account) व्यापार संतुलन, शुद्ध कारक आय और शुद्ध अंतरण भुगतान (net transfer payments) का योग होता है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?**

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q.4) Solution (c)**

जुड़वां घाटे (twin deficits) की परिकल्पना, जिसे डबल डेफिसिट परिकल्पना या ट्विन डेफिसिट विसंगति भी कहा जाता है, एक व्यापक आर्थिक संबंध है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के चालू खाता शेष और उसके सरकार के बजट संतुलन के बीच एक मजबूत संबंध है।

यह परिकल्पना कहती है कि जैसे-जैसे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है; इसका व्यापार घाटा (यानी निर्यात और आयात के बीच का अंतर) भी बढ़ जाता है। इसलिए, जब किसी देश की सरकार जितना राजस्व अर्जित करती है, उससे अधिक व्यय करती है, तो देश निर्यात से अधिक आयात करना भी आरंभ कर देता है। चालू खाता (Current Account), व्यापार संतुलन, शुद्ध कारक आय (जैसे ब्याज और लाभांश) और शुद्ध अंतरण भुगतान (जैसे विदेशी सहायता) का योग है।

**Source:** <https://www.thehindu.com/business/Economy/indias-trade-deficit-with-china-dips-to-4866-billion-in-fy20/article31973598.ece>

**Q.5) निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति (Trinity of Carnatic music) माना जाता था या उन्हें 'कर्नाटक संगीत के तीन रत्न' के नाम से भी जाना जाता है?**

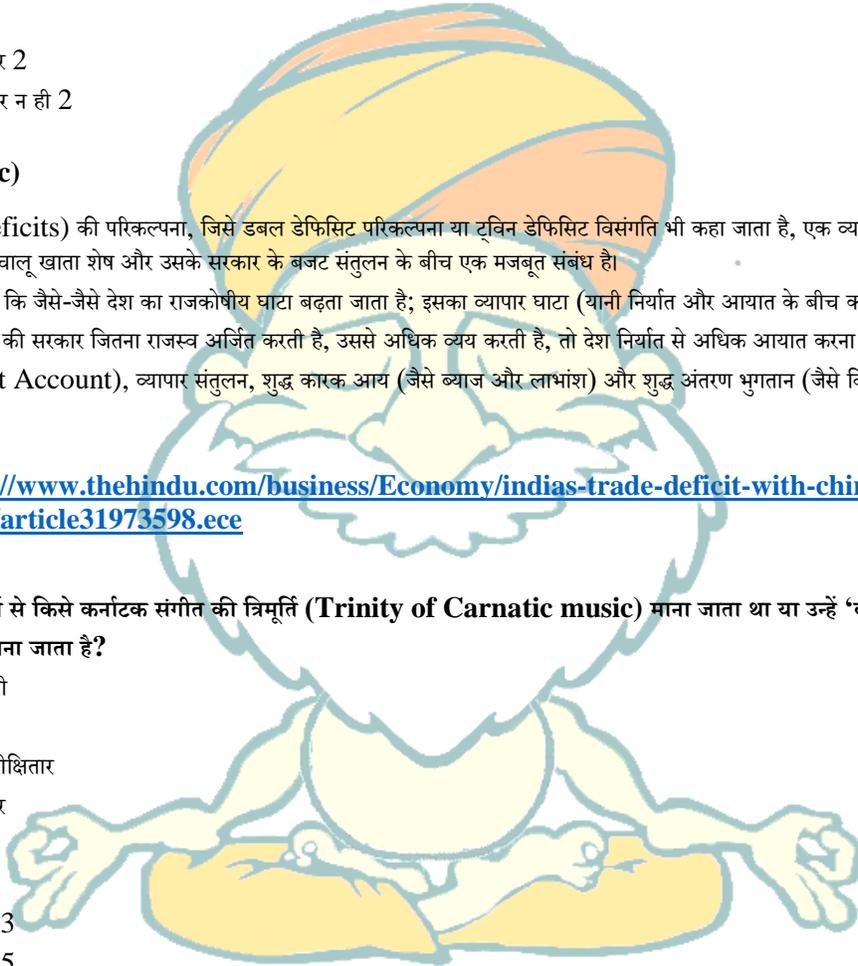
1. श्यामा शास्त्री
2. त्यागराज
3. मुथुस्वामी दीक्षितार
4. तोल्काप्पियर
5. तिरुवल्लुवर

**सही उत्तर चुनें:**

- a) 1, 2 और 3
- b) 2, 4 और 5
- c) 2, 3 और 5
- d) 1, 4 और 5

**Q.5) Solution (a)**

कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, जिसे कर्नाटक संगीत के तीन रत्न के रूप में भी जाना जाता है, 18 वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत के संगीतकार की उत्कृष्ट तिकड़ी का उल्लेख करता है, जो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री हैं।



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

**Source:** <https://www.thehindu.com/entertainment/music/kritis-with-a-healing-touch/article31971313.ece>

**Q.6)** अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में दो प्रजातियों - स्ट्रीड्ड हेयरस्ट्रीक (Striped Hairstreak) और इल्यूसिव प्रिंस (Elusive Prince) की खोज की गई। ये किसकी प्रजातियां हैं -

- सांप
- प्रवासी पक्षी
- तितलियों
- मेंढक

### Q.6) Solution (c)

लेपिडोप्टेरिस्ट्स (Lepidopterists) ने अरुणाचल प्रदेश में तितलियों की दो प्रजातियों - स्ट्रीड्ड हेयरस्ट्रीक (Striped Hairstreak) और इल्यूसिव प्रिंस (Elusive Prince) की खोज की है।

स्ट्रीड्ड हेयरस्ट्रीक को सबसे पहले चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीटविज्ञानशास्त्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इल्यूसिव प्रिंस का वियतनामी संबंध है और पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला ब्लैक प्रिंस माना जाता है।

स्ट्रीड्ड हेयरस्ट्रीक विजयनगर में म्यांमार की सीमा में देखी गयी, जबकि इल्यूसिव प्रिंस को मायाओ में नामदाफा नेशनल पार्क की परिधि में पाया गया था।

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/national/japanese-found-chinese-butterfly-is-now-indian/article31963607.ece>

**Q.7)** सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य (Sakteng wildlife sanctuary) के दावों पर विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ संबंधित है?

- चीन और भूटान
- भारत और नेपाल
- नेपाल और भूटान
- चीन और नेपाल

### Q.7) Solution (a)

भूटान ने पूर्वी भूटान में सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य में चीनी दावों का विरोध करते हुए एक सीमांकन भेजा था।

चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) से सकतेंग अभयारण्य के लिए फंडिंग को रोकने का प्रयास किया, इस आधार पर कि यह "विवादित" क्षेत्र है।

सकतेंग अभयारण्य को इससे पहले चीन द्वारा बिना किसी आपत्ति के मिट्टी के कटाव को रोकने की परियोजना के लिए 2018-2019 सहित ऐसे कई अनुदान प्राप्त हुए हैं।

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/international/days-after-demarche-china-doubles-down-on-claims-on-eastern-bhutan-boundary/article31993470.ece>

**Q.8)** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (sexual and reproductive health) एजेंसी है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह की सदस्य है तथा इसकी कार्यकारी समिति का हिस्सा है।
- UNFPA संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित है तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा इसका जनादेश (mandate) स्थापित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- केवल 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 2
- 1, 2 और 3

### Q.8) Solution (c)

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है तथा एक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) से अपना जनादेश स्थापित करता है।
- इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था और 1969 में परिचालन आरंभ किया गया था। 1987 में, इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया था, लेकिन जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के लिए मूल संक्षिप्त नाम, 'UNFPA' को बरकरार रखा गया था।
- यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित नहीं है, इसके बजाय, यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, फाउण्डेशंस और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।
- UNFPA स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लैंगिक समानता (SDG5) पर सतत विकास लक्ष्य से निपटने के लिए सीधे काम करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समूह का सदस्य है तथा इसकी कार्यकारी समिति का हिस्सा है।

Source: <https://www.unfpa.org/about-us>

<https://www.thehindu.com/news/national/india-accounts-for-458-million-of-the-worlds-missing-females-says-un-report/article31951401.ece>

Q.9) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना किसका हिस्सा है -

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
- मौलिक कर्तव्य
- मौलिक अधिकार
- प्रस्तावना

### Q.9) Solution (a)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत)

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य इसके लिए प्रयास करेगा -

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;
- राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना;
- एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान; तथा
- मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना

Source: <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/will-accept-marines-case-ruling-centre/article31985141.ece>

Q.10) रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

- यह रक्षा खरीद पर सरकार का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

3. इसे 2009 में मुंबई हमले के बाद के सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 2
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

### Q.10) Solution (b)

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council)

- डीएसी रक्षा मंत्रालय का सबसे उच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- रक्षा क्षेत्र में कारगिल पश्चात् सुधारों के रूप में 2001 में इसे स्थापित किया गया था।
- डीएसी की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद का उद्देश्य आवंटित बजट संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, निर्धारित क्षमताओं और निर्धारित समय सीमा के अनुसार सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना है।

Source: <https://www.thehindu.com/news/national/mod-approves-33-new-fighter-jets-for-iaf-in-deals-worth-38900-crore/article31971510.ece>

Q.11) विश्व बैंक समूह द्वारा 2030 तक हासिल करने के लिए, विश्व बैंक समूह द्वारा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन से दो लक्ष्य हैं?

- चरम गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना
- गरीबी को समाप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना
- संपूर्ण गरीबी को समाप्त करना तथा शून्य भूखमरी के साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान करना
- चरम गरीबी को समाप्त करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

### Q.11) Solution (a)

विश्व बैंक समूह ने 2030 तक विश्व के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एक दिन में \$ 1.90 से कम में जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रतिशत को कम करके चरम गरीबी को समाप्त करना, जिसे अधिकतम 3% तक सीमित किया जायेगा।
- प्रत्येक देश के लिए निचले 40% की आय वृद्धि को बढ़ावा देकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देना

Source: <https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1636790>

<https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do>

Q. 12) निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का गठन करते हैं?

- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें:

- 1, 2 और 3
- 1 और 2
- 3 और 4

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

d) 1, 2, 3 और 4

### Q. 12) Solution (a)

विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक समूह, विश्व के विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण और ज्ञान के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

इसकी पाँच संस्थाएँ गरीबी को कम करने, साझा समृद्धि बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता साझा करती हैं। यह निम्नलिखित हैं

1. IBRD- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक
2. IDA- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
3. IFC- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
4. MIGA- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी
5. ICSID- निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

Link: [The IMF and the World Bank: How Do They Differ?](#)

### Q. 13) खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है
2. भारत एफएओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है
3. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 2
- d) 1, 2 और 3

### Q. 13) Solution (c)

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी समाप्त करने तथा पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।

भारत FAO के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है।

Source: <https://indianexpress.com/article/explained/the-difference-between-a-locust-plague-upturge-and-outbreak-6492132/>

### Q. 14) 2019 में, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को आतंकवाद की कार्यवाही से अर्जित संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार दिया है।
2. इसने एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 14) Solution (c)

हाल ही में, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार -

- व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में घोषित किया जा सकता है तथा उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है।
- यह ऐसे व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान करता है, जब उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाता है।
- संशोधनों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को आतंकवाद की कार्यवाही से अर्जित संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार दिया है।
- इससे पहले, कानून में आवश्यकता थी कि एनआईए संबंधित राज्य के पुलिस प्रमुख से आतंकवाद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व अनुमति ले।
- इससे पहले, उप पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारियों को धारा 43 के अनुसार यूएपीए के तहत मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया था। अब, निरीक्षक (inspector) रैंक के अधिकारियों को ऐसा करने का अधिकार है।
- निरीक्षक-रैंक के अधिकारियों ने समय के साथ UAPA से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त दक्षता हासिल कर ली है तथा इस कदम से ऐसे मामलों में न्याय प्रदान करने में तेजी आएगी, जिनकी समीक्षा विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

Source: <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/govt-blocks-40-websites-of-sikhs-for-justice/article31997918.ece>

### Q. 15) वैश्विक प्रकोप चेतावनी और प्रतिक्रिया नेटवर्क (Global Outbreak Alert and Response Network -GOARN)

किसकी एक पहल है -

- a) खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
- b) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
- c) विश्व बैंक समूह
- d) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

### Q. 15) Solution (b)

वैश्विक प्रकोप चेतावनी और प्रतिक्रिया नेटवर्क (GOARN) एक नेटवर्क है जो कई तकनीकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, प्रयोगशालाओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों से गठित है जो कि महामारी के खतरे को देखने और प्रतिक्रिया करने के लिए कार्य करते हैं।

GOARN विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर्गत कार्य करता है, जो इसके सबसे उल्लेखनीय साझेदारों में से एक है। इसके लक्ष्य हैं: रोगों की जांच करना और उनका अध्ययन करना, उन जोखिमों का मूल्यांकन करना जो कुछ बीमारियों को पैदा करते हैं, तथा बीमारियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षमता में सुधार करना।

Source: <https://www.thehindu.com/sci-tech/health/the-hindu-explains-what-are-scientists-saying-about-a-new-virus-strain-in-china/article31991105.ece>

### Q.16) मनरेगा के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अकुशल मैन्युअल काम करने के इच्छुक घर (Household) के केवल एक वयस्क सदस्य को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने का अधिकार है।
2. यह मांग प्रेरित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है तथा केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग पर आधारित है।
3. मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार (legal entitlement) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

- a) 1 और 2

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

### Q.16) Solution (c)

मनरेगा का अधिकार वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने का है, जहाँ प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल मैनूअल काम करते हैं।

"घरेलू" (Household) का अर्थ रक्त, विवाह या गोद लेने और आम तौर पर एक साथ रहने और भोजन साझा करने या एक सामान्य राशन कार्ड द्वारा एक दूसरे से संबंधित परिवार के सदस्य है।

सरल शब्दों में, मनरेगा में अकुशल रोजगार पाने के इच्छुक वयस्क सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मनरेगा मांग प्रेरित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है तथा केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग पर आधारित होता है।

एक संभावित घर से नौकरी के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार के लिए प्रावधान की विफलता के परिणामस्वरूप रोजगार चाहने वालों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार दिया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

**Source:** <https://www.thehindu.com/todays-paper/14-lakh-families-reach-mgnregas-annual-work-limit/article32008031.ece>

### Q.17) निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

1. 2018 में, अफीम की खेती के मामले में भारत शीर्ष पांच में शामिल है।
2. वैश्विक अवैध अफीम उत्पादन में 90% से अधिक एशिया का भाग है।
3. अफगानिस्तान विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 3
- b) 2 और 3
- c) 1 और 2
- d) 1, 2 और 3

### Q.17) Solution (b)

अफीम का अवैध रूप से लगभग 50 देशों में उत्पादन किया जाता है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में अफीम के कुल वैश्विक उत्पादन का 97% केवल 3 देशों से आया (अफगानिस्तान में 84%, म्यांमार में 7% और मेक्सिको में 6% की हिस्सेदारी है)।

2018 में अफीम की जब्ती (seizure) के मामले में भारत शीर्ष पांच (चौथे स्थान) पर है, अफीम उत्पादन में नहीं। इसलिए, कथन 1 गलत है।

एशिया वैश्विक अवैध अफीम उत्पादन के 90% से अधिक की मेजबानी करता है तथा विश्व का सबसे बड़ा खपत बाजार है। कुल अफीम का 84% अफगानिस्तान में उत्पादित किया गया था।

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/national/fourth-highest-opium-seizure-in-2018-reported-from-india-world-drug-report/article32005672.ece>

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

**Q.18) बुबोनिक प्लेग (Bubonic plague) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो हाल ही में समाचारों में था?**

- यह एक जूनोटिक बीमारी (zoonotic disease) है तथा कृन्तकों से पिस्सू द्वारा (by fleas from rodents) प्रेषित एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है।
- यह एक स्वाइन फ्लू स्ट्रेन है जिसमें वायरस के समान जीन होते हैं, जो 2009 फ्लू (H1N1) महामारी का कारण बना।
- यह विषाणुओं का एक परिवार है जो मुख्य रूप से कृन्तकों द्वारा फैलता है।
- यह अनियंत्रित प्रजनन टिड्डी आबादी की सबसे गंभीर श्रेणी के लिए संदर्भित है।

**Q.18) Solution (a)**

**बुबोनिक प्लेग क्या है?**

- यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो कृन्तकों से पिस्सू द्वारा प्रेषित होता है।
- यह एक जूनोटिक बीमारी है तथा इसे अन्य जानवरों या मनुष्यों में प्रेषित किया जा सकता है।
- यह मुख्य रूप से एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है।
- यह मृत प्लेग संक्रमित जानवर से शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप भी हो सकता है।
- यह जीवाणु यर्सिनिया पेस्टिस (Yersinia pestis) के कारण होने वाले तीन प्लेगों में से एक है। अन्य दो सेप्टिकेमिक प्लेग (Septicaemic plague) और न्यूमोनिक प्लेग (Pneumonic plague) हैं।
- यह यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है तथा तत्काल अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह 24 घंटे से कम समय में एक वयस्क को मार सकता है।

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/international/suspected-case-of-bubonic-plague-found-in-chinas-inner-mongolia/article31998748.ece>

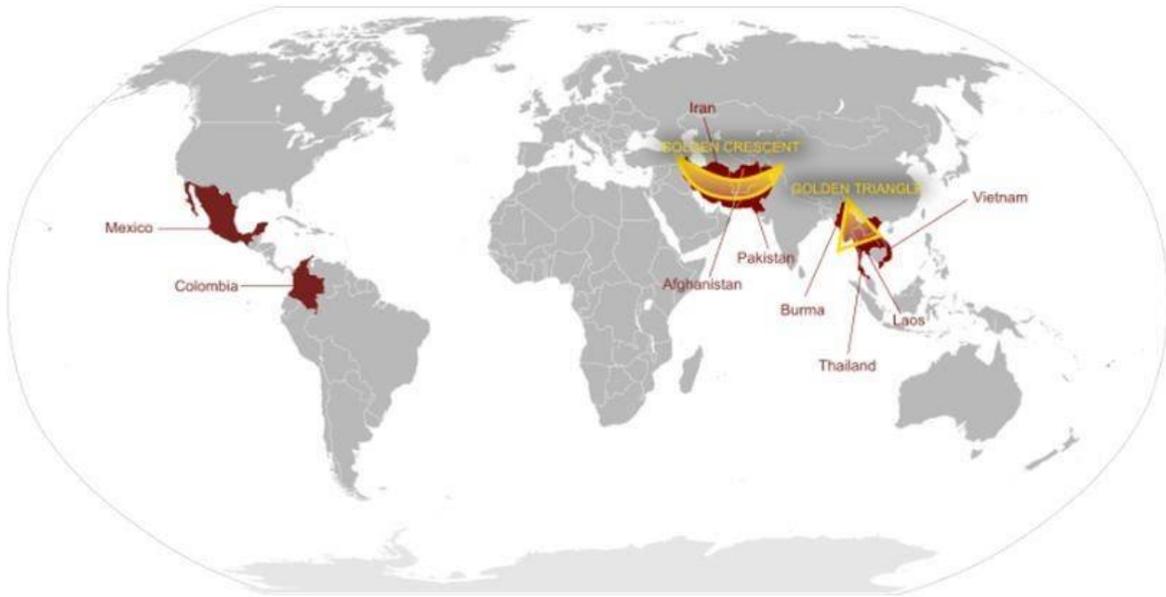
**Q.19) गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है?**

- उग्रवाद, आतंकवाद और तस्करी से प्रभावित क्षेत्र
- पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण विसंगतियाँ (Gravitational anomalies)
- चीन की मोतियों की माला (string of Pearls) रणनीति के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति-रणनीति
- विश्व में अवैध ड्रग्स उत्पादक क्षेत्र

**Q.19) Solution (d)**

भारत का रणनीतिक स्थान दक्षिण एशिया में अवैध ड्रग्स के दो सबसे बड़े स्रोतों के मध्य है- उत्तर-पूर्व में गोल्डन क्रीसेंट (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) तथा उत्तर-पूर्व में कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, थाईलैंड और लाओस)।





**Pic: Opium Cultivation**

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/national/fourth-highest-opium-seizure-in-2018-reported-from-india-world-drug-report/article32005672.ece>

**Q.20) वेस्ट बैंक (West Bank) से किसकी सीमा मिलती है -**

1. इजराइल
2. सीरिया
3. मृत सागर
4. जॉर्डन
5. लेबनान

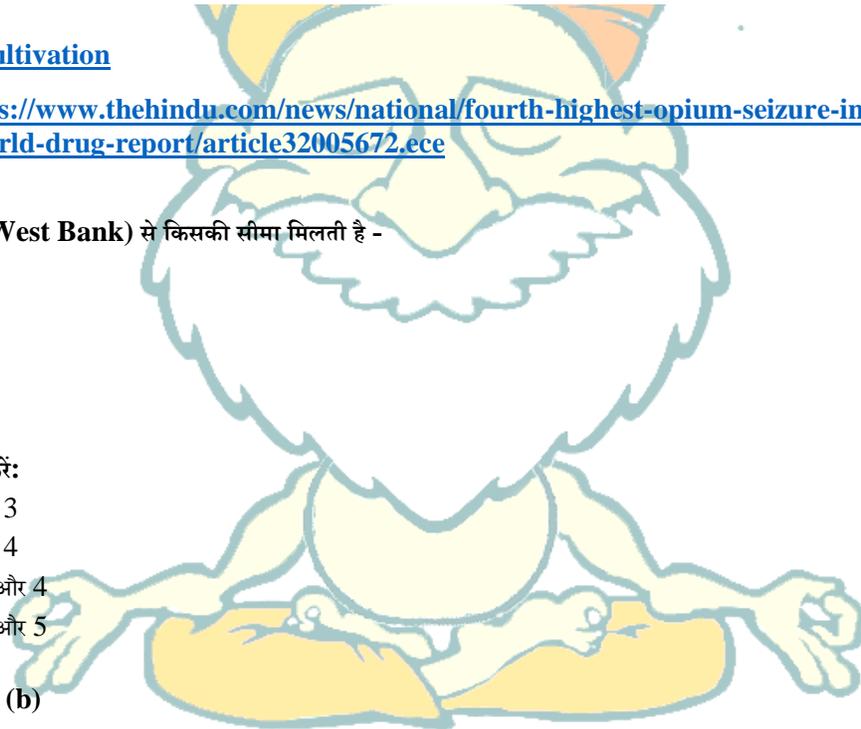
**सही उत्तर का चयन करें:**

- a) 1, 2 और 3
- b) 1, 3 और 4
- c) 1, 2, 3 और 4
- d) 1, 3, 4 और 5

**Q.20) Solution (b)**

वेस्ट बैंक पश्चिमी एशिया के भूमध्यसागरीय तट के समीप एक भूभागीय क्षेत्र है, जो पूर्व में जॉर्डन द्वारा तथा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में इजरायल द्वारा सीमाबद्ध है। वेस्ट बैंक का कुछ क्षेत्र पश्चिमी मृत सागर से भी सीमाबद्ध है।

मानचित्र का निरीक्षण करें -





Pic: [West Bank](#)

Q.21) निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक की राज्य तितली (state butterfly) माना जाता है?

- दक्षिणी बर्डविंग (Southern Birdwing)
- गोल्डन बर्डविंग (Golden Birdwing)
- स्ट्रीप्ड हेयरस्ट्रीक (Striped Hairstreak)
- गोल्डन बटरफ्लाई (Golden Butterfly)

Q.21) Solution (a)

दक्षिणी बर्डविंग, जिसका वैज्ञानिक नाम *Troides minos* है, के पास 140-190 मिमी के पंख होते हैं, जिसे भारत में सबसे बड़ा तितली माना जाता था।

राज्य तितली चुनने वाला कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है।

दक्षिणी बर्डविंग को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसका रंग कर्नाटक ध्वज के रंगों से मेल खाता था।

क्या आप जानते हैं?

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- गोल्डन बर्डिंग नामक एक हिमालयी तितली अब 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली बन गयी है। गोल्डन बर्डिंग दक्षिणी बर्डिंग से बड़ी है, जिसे पहले सबसे बड़ा माना जाता था।

**Source:** <https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/himalayan-butterfly-is-indias-largest-after-88-years/article32012652.ece>

**Q.22) पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) के बारे में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें**

- इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है
- यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर स्थित है
- यह एक खारे पानी (brackish water) की झील है

सही कथनों का चयन करें

- 1 और 2
- 2 और 3
- 1 और 3
- 1, 2 और 3

**Q.22) Solution (b)**

पैंगोंग झील अर्थात पैंगोंग त्सो

- यह हिमालय में एक बन्द जलसम्भर झील (endorheic lake) है।
- पैंगोंग झील की लंबाई का लगभग 60% तिब्बत में स्थित है।
- हालांकि यह एक खारे पानी की झील है, लेकिन यह पूरी तरह से सर्दियों के दौरान जम जाती है।
- पैंगोंग झील के खारे पानी में बहुत निम्न सूक्ष्म वनस्पति हैं। कथित तौर पर, झील में, सिवाय क्रस्टेशियंस (crustaceans) के कोई मछली या कोई जलीय जीवन नहीं मिलते हैं।
- झील रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में जाने जाने की प्रक्रिया में है। यह कनवेंशन के तहत दक्षिण एशिया में पहली सीमा-पारीय (ट्रांस-बाउंड्री) आर्द्रभूमि होगी।

पैंगोंग झील एक विवादित क्षेत्र है। वास्तविक नियंत्रण रेखा झील से होकर गुजरती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किमी दूर झील का एक हिस्सा चीन द्वारा नियंत्रित है लेकिन भारत द्वारा दावा किया जाता है। पूर्वी छोर तिब्बत में है और भारत इस पर दावा नहीं करता है। पश्चिमी छोर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है।

**Q.23) कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

- यह अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central sector scheme) है।
- योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2022 (2 वर्ष) तक होगी।
- यह फसल-पूर्व (pre-harvest) और कटाई के पश्चात् (post-harvest) के बुनियादी ढांचे के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1, 2 और 3

**Q.23) Solution (a)**

कृषि अवसंरचना कोष

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना -कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इस योजना के बाद फसल प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक होगी।
- कृषि-उद्यमियों, स्टार्ट-अप, कृषि -तकनीकी अभिकर्ताओं और बुनियादी सुविधाओं तथा रसद सुविधाओं के लिए किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि-अवसंरचना कोष के साथ है।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637221>

**Q.24) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:**

(ऑपरेशन का नाम):: (संबद्धता)

1. ऑपरेशन सद्भावना (Operation Sadbhavna): वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ तनाव में कमी लाने हेतु
2. ऑपरेशन समुद्र सेतु (Operation Samudra Setu):: COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा
3. ऑपरेशन सुकून (Operation Sukoon):: जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में आतंकवाद-रोधी रणनीति

ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी सही है / हैं?

- a) केवल 2
- b) केवल 3
- c) 1 और 2
- d) 1, 2 और 3

**Q.24) Solution (a)**

ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में 05 मई 2020 को आरंभ किया गया था, 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से वापस लाने के बाद सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है।

ऑपरेशन सद्भावना - सेना ने जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अनूठी मानवीय पहल की। ऑपरेशन पहल करने और राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ 'आम-जन' को फिर से एकीकृत करने के लिए आतंकवाद-रोधी रणनीति का एक हिस्सा है।

ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन राहत पहले पूर्व में 2006 और 2015 में क्रमशः इसी तरह के निकासी ऑपरेशन किए गए थे।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637314>

**Operation Sadbhavna – Picked from India Year Book, 2020**

**Q.25) 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ)' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।**

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कानून संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XIV द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की।
2. इसमें यूएनएससी के स्थायी सदस्यों द्वारा नौ वर्ष के लिए चुने गए पंद्रह न्यायाधीश होते हैं

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

### Q.25) Solution (a)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कानून संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XIV द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ न्यायाधीशों के पद के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। ये अंग एक साथ लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए, एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहिए। न्यायालय के भीतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में पांच न्यायाधीशों का चुनाव होता है। यदि किसी न्यायाधीश की पद पर आसीन रहते हुए मृत्यु होती है, इस पद को पूरा करने के लिए आम तौर पर एक विशेष चुनाव में न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है।

कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते।

### Q.26) नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा / से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संबंध में सही है?

1. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित, वित्तीय विधान (financial legislation) से संबंधित कानून है।
2. अधिनियम के तहत, विदेशों से धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक पांच वर्ष में स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।

सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.26) Solution (b)

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)

- यह विदेशी अंशदान (विशेषकर मौद्रिक दान) को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून है।
- एफसीआरए अधिनियम 2010 के अनुसार, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- अधिनियम के तहत, संगठनों को प्रत्येक पांच वर्ष में स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।
- चूंकि अधिनियम, वित्तीय कानून से संबंधित कानून होने के बावजूद, आंतरिक सुरक्षा कानून है, यह गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के।

Source: <https://www.thehindu.com/todays-paper/three-ngos-linked-to-congress-under-home-ministry-scanner/article32026705.ece>

### Q.27) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने के लिए है।
2. इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा, 24 \* 7 बिजली की आपूर्ति और पहुंच के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है।
3. PMAY (U) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर का मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) 1 और 3
- b) केवल 3
- c) 1 और 2
- d) 1, 2 और 3

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

### Q.27) Solution (c)

शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015-2022 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 25 जून 2015 को आरंभ की गई थी।

यह योजना वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने के लिए है।

मिशन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय पात्रता प्रदान करता है, जो सभी लगभग 1.12 करोड़ पात्र परिवारों / लाभार्थियों को घरों की वैध मांग के सापेक्ष आवास प्रदान करते हैं।

PMAY (U) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। हालांकि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन में घरों के आकार को बढ़ाने के लिए लचीलापन है।

पूर्ववर्ती योजनाओं के विपरीत EWS और LIG की महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में सरकार के इस प्रयास को जारी रखते हुए, PMAY (U) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर की मालिक या सह-मालिक होने का एक अनिवार्य प्रावधान किया है।

इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरित (converged) किया गया है ताकि घरों में शौचालय, सहज योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग की सुविधा, आदि सुनिश्चित हो सके।

**Source:** <https://www.thehindu.com/news/national/cabinet-nod-for-development-of-affordable-rental-housing-complexes-for-urban-migrants-poor/article32022523.ece>

<https://pmay-urban.gov.in/about>

### Q.28) संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से कौन से अंग हैं?

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
2. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court)
3. आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council)
4. न्यास परिषद (Trusteeship Council)

सही उत्तर चुनें:

- a) 1 और 2
- b) 3 और 4
- c) 1, 3 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

### Q.28) Solution (c)

संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंग हैं:

- **महासभा (General Assembly):** संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्धारण और प्रतिनिधि अंग
- **सुरक्षा परिषद (Security Council):** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी
- **आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council):** समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय
- **न्यास परिषद (Trusteeship Council):** 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करता है जो सात सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था। हालांकि, 1 नवंबर 1994 को इसके संचालन को निलंबित कर दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice):** संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- **सचिवालय (Secretariat):** महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के दिन-प्रतिदिन के कार्य को पूरा करता है

### Q.29) संयुक्त राष्ट्र के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के दो विवाद समाधान तंत्र हैं।
2. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र, यूनेस्को के भी सदस्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.29) Solution (d)

नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना है।

यूनेस्को के तीन सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश नहीं हैं: कुक आइलैंड्स, नीयू (Niue), और फिलिस्तीन (फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक गैर-सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य है जो 29 नवंबर 2012 से है), जबकि एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य (लिचेंस्टीन) यूनेस्को का सदस्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसके पास जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोप वाले व्यक्तियों पर जनादेश है। यह नीदरलैंड के हेग में बैठता है।

न्यायालय की स्थापना रोम संविधि (Rome Statute) द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस संधि पर बातचीत की गई थी; हालांकि, इसे संयुक्त राष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय बनाया गया।

### Q.30) अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes -ARHCs) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था?

- a) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ARHCs का शुभारंभ किया है।
- b) ARHCs प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप-योजना है।
- c) ARHCs के लिए लाभार्थी EWS/ LIG श्रेणियों से शहरी प्रवासी / गरीब होंगे।
- d) इनमें से कोई भी नहीं।

### Q.30) Solution (d)

प्रवासियों कामगारों / शहरी गरीबों के लिए अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs)

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स/ किफायती किराया आवासीय परिसर (ARHCs) की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना है।
- यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी प्रवासियों / गरीबों को रहने की सुगमता प्रदान करेगा तथा उन्हें अपने कार्यस्थल के करीब गरिमापूर्ण किफायती किराये के आवास की सुविधा प्राप्त होगी।

**ARHC योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी:**

- मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित करना
- सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव

ARHCs के लिए लाभार्थी EWS/ LIG श्रेणियों से शहरी प्रवासी / गरीब होंगे। ARHCs सभी सामान्य सुविधाओं सहित एकल बेडरूम आवासीय इकाइयों और 4/6 बिस्तरों के शयनगृह (Dormitory) का मिश्रण होगा, जो विशेष रूप से 25 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए किराये के आवास के लिए उपयोग किया जाएगा।

# IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

Source: <https://pmay-urban.gov.in/arhc-about>

<https://www.thehindu.com/news/national/cabinet-nod-for-development-of-affordable-rental-housing-complexes-for-urban-migrants-poor/article32022523.ece>

**Q.31)** अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक हिस्सा है।
2. AAY के तहत, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार है।
3. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 2
- b) 1 और 2
- c) 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

**Q.31) Solution (d)**

अंत्योदय अन्न योजना

- लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।
- यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विकसित की गई थी।
- उद्देश्य - सबसे गरीब आबादी को लक्षित करना और उन्हें भूख से राहत प्रदान करना।
- यह एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक हिस्सा है तथा एएवाई के तहत प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।
- कवरेज - यह राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कवर किए गए बीपीएल परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों को कवर करता है तथा उन्हें, 2 रूपए / प्रति किग्रा गेहूं के लिए और चावल के लिए 3 रूपए / प्रति किलो, 1 रूपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की उच्च रियायती दर पर अनाज प्रदान करता है।

Source: <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/free-grains-will-be-given-till-aug-31/article32037395.ece>

<https://dfpd.gov.in/pds-aay.htm>

**Q.32)** निम्नलिखित में से कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमाएँ साझा करते हैं?

1. सिक्किम
2. पश्चिम बंगाल
3. बिहार
4. उत्तराखंड
5. हिमाचल प्रदेश

सही उत्तर चुनें:

- a) 1, 3 और 4
- b) 1, 2, 3 और 4
- c) 1, 3, 4 और 5
- d) 1, 2, 3, 4 और 5

**Q.32) Solution (b)**

नेपाल पांच भारतीय राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किमी से अधिक की सीमा साझा करता है।



**Q.33)** निम्नलिखित में से कौन से देश जून 2019 तक "मालाबार अभ्यास" (Malabar Exercise) के स्थायी भागीदार हैं?

1. भारत
2. अमेरिका
3. जापान
4. ऑस्ट्रेलिया
5. यूनाइटेड किंगडम

सही उत्तर चुनें:

- a) 1, 2 और 4
- b) 1, 2 और 3
- c) 1, 2 और 5
- d) 1, 2, 3 और 4

**Q.33) Solution (b)**

अभ्यास मालाबार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत का स्थायी साझेदार के रूप में एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है।

मूल रूप से 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आरंभ हुआ, 2015 में जापान एक स्थायी भागीदार बन गया।

जापान और यू.एस. के साथ मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय भारत को लेना है।

**Source:** <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/india-to-take-call-on-australias-inclusion-in-malabar-exercises/article32037392.ece>

**Q.34)** रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट (Rewa Ultra Mega Solar Power project:) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एशिया की सबसे बड़ी बिजली परियोजना है।
2. यह राजस्थान में स्थित एक परिचालन सौर पार्क है।
3. भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से 100 गीगावॉट शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) 1 और 3
- b) केवल 1

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

### Q.34) Solution (a)

रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना

- प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई को देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया।
- अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है जब भारत ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरा करेगा।

रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन उस दिशा में हुई प्रगति को बढ़ाएगा क्योंकि भारत पर्यावरण के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निर्भरता के लिए एक मार्ग पर चलना जारी रखता है।

Source: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637549>

### Q.35) नीचे दिए गए कथन में से कौन सा ताइवान के संबंध में सही है / हैं?

1. यह सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का सदस्य नहीं है।
2. यह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और फिलीपीन सागर के आसपास स्थित है।

सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.35) Solution (c)

ताइवान, आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य, पूर्वी एशिया का एक देश है। पड़ोसी देशों में उत्तर-पश्चिम में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन), उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस शामिल हैं।

23.7 मिलियन निवासियों के साथ, ताइवान सबसे घनी आबादी वाले देशों में से है, और सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का सदस्य नहीं है।

यह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और फिलीपीन सागर के आसपास स्थित है। (नीचे मानचित्र देखें)



# IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5



**STATIC QUIZ**

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

### Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख चंद्रगुप्त प्रथम का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
2. फाह्यान ने चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.1) Solution (c)

इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

फाह्यान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. गुप्त काल में संधिविग्रह (Sandivigraha) उस अधिकारी का नाम था, जो किसानों से कर एकत्र करता था।
2. गुप्त काल में प्रांतीय गवर्नरों को भुक्ति (Bhuktis) कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.2) Solution (d)

गुप्तकालीन शिलालेखों में संधिविग्रह (Sandivigraha) का उल्लेख किया गया था, जो विदेश मामलों के मंत्री थे।

इसलिए कथन 1 गलत है।

गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्तियों तथा प्रांतीय गवर्नरों को उपरिक (Uparikas) के रूप में जाना जाता था।

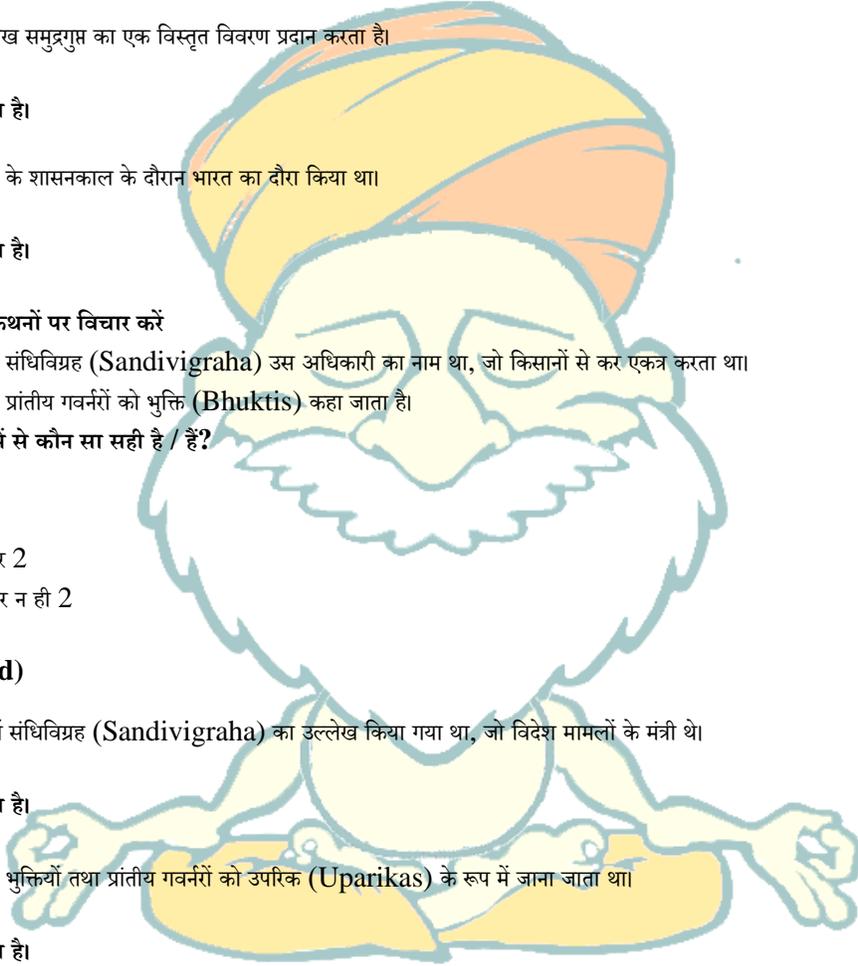
इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. गुप्त काल की तुलना में हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वृद्धि हुई थी।
2. उपन्यास कदंबरी को हर्षवर्धन ने लिखा था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2



### Q.3) Solution (d)

गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था की तुलना में हर्षवर्धन के काल में तीव्र आर्थिक गिरावट आई थी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उपन्यास कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी और यह कार्य उनके पुत्र भुषणभट्ट ने पूरा किया था।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था।
2. धर्म पर आधारित विषयों को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अनुमति नहीं थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.4) Solution (c)

गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसे उनके उत्तराधिकारियों और बाद में हर्ष द्वारा संरक्षण दिया गया था।

इसलिए कथन 1 गलत है।

नालंदा विश्वविद्यालय में वेदों, हीनयान सिद्धांत, महायान सिद्धांत, सांख्य और योग दर्शन जैसे विभिन्न धार्मिक विषयों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा, तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला जैसे सामान्य विषय पाठ्यक्रम में थे।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर की ओर नियंत्रण करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पाल और पल्लवों के बीच एक शताब्दी तक चलने वाले लंबे संघर्ष का नाम है।
2. कन्नौज और गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष हुआ था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

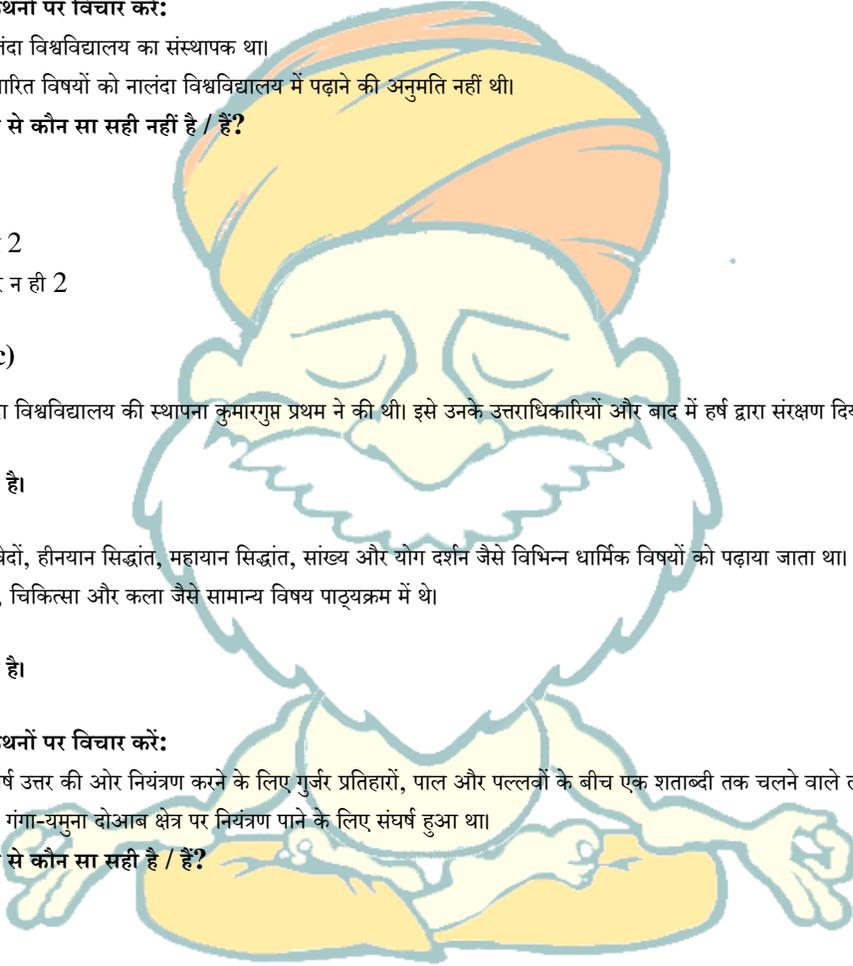
- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.5) Solution (b)

त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच था।

इसलिए कथन 1 गलत है।

कन्नौज और गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष हुआ था।



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q.6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. मामल्लपुरम में तटीय मंदिर (shore temple) नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था।
2. नरसिंहवर्मन द्वितीय ने संस्कृत नाटक मतविलासप्रहसनम् (Mattavilasaprahasanam) लिखा है।
3. पल्लव काल में बौद्ध विहार को दिए गए भूमि अनुदान देवदान (Devadhana) के नाम से जाने जाते हैं।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

**Q.6) Solution (a)**

मामल्लपुरम में तटीय मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय (राजसिम्हा) द्वारा बनवाया गया था।

इसलिए कथन 1 सही है।

महेंद्रवर्मन प्रथम ने संस्कृत नाटक मतविलासप्रहसनम् लिखा है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

पल्लव काल में मंदिरों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को देवदान के नाम से जाना जाता है।

इसलिए कथन 3 गलत है।

**Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. फा-ह्यान के अनुसार, गुप्त काल में दंड बहुत गंभीर (very severe) थे।
2. फा-ह्यान का उल्लेख है कि गुप्त काल में चांडाल को समाज से पृथक कर दिया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q.7) Solution (b)**

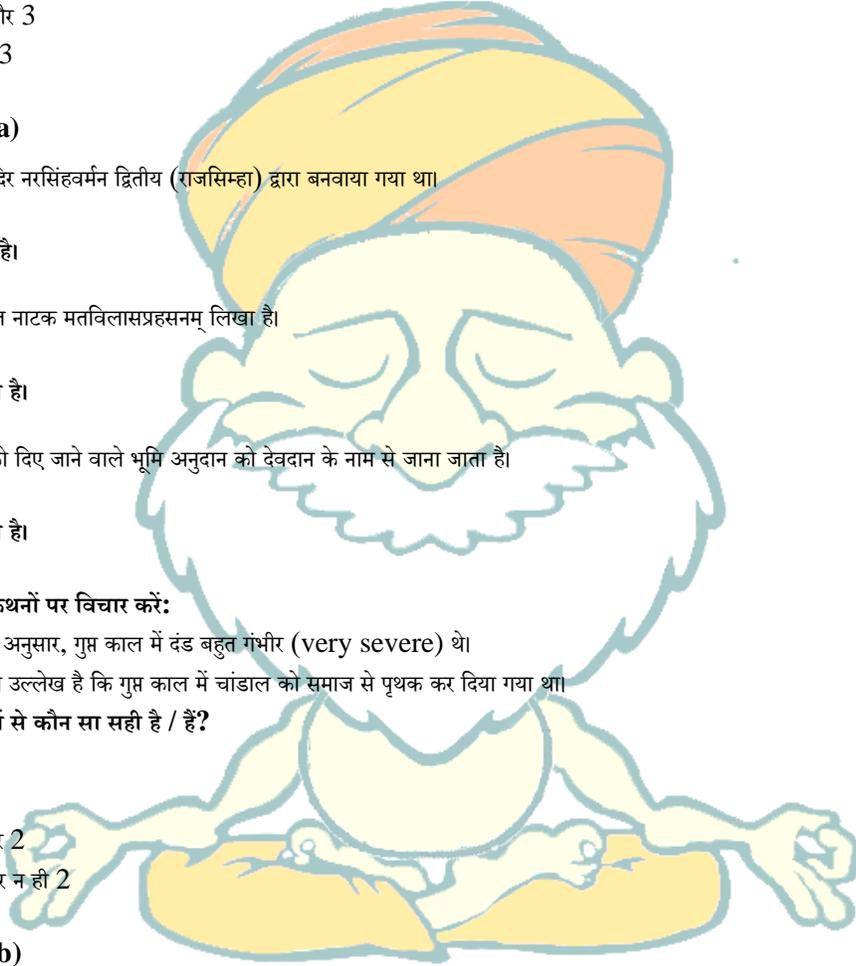
फा-ह्यान के अनुसार, गुप्त काल में दंड गंभीर नहीं थे। जुर्माना वसूलना एक सामान्य सजा थी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

फा-ह्यान का उल्लेख है कि गुप्त काल में चांडाल को समाज से पृथक कर दिया गया था।

अतः कथन 2 सही है।

**Q.8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

1. चालुक्य प्रशासन पल्लवों और चोलों की तुलना में अत्यधिक विकेंद्रीकृत था।
2. बादामी चालुक्य ब्राह्मणवादी हिंदू थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.8) Solution (b)

चालुक्य प्रशासन पल्लवों और चोलों के विपरीत अत्यधिक केंद्रीकृत था।

इसलिए कथन 1 गलत है।

बादामी चालुक्य ब्राह्मणवादी हिंदू थे।

इसलिए कथन 1 सही है।

### Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वेसर शैली चालुक्यों के अधीन अपनी चरम परिणति (culmination) तक पहुँच गई थी।
2. राष्ट्रकूटों के काल में वैष्णववाद और शैववाद के हिंदू संप्रदाय फलते-फूलते रहे थे।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.9) Solution (b)

वेसर शैली राष्ट्रकूट और होयसल के अंतर्गत अपनी चरम परिणति तक पहुंची थी।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रकूटों के काल में वैष्णववाद और शैववाद के हिंदू संप्रदाय फलते-फूलते रहे थे।

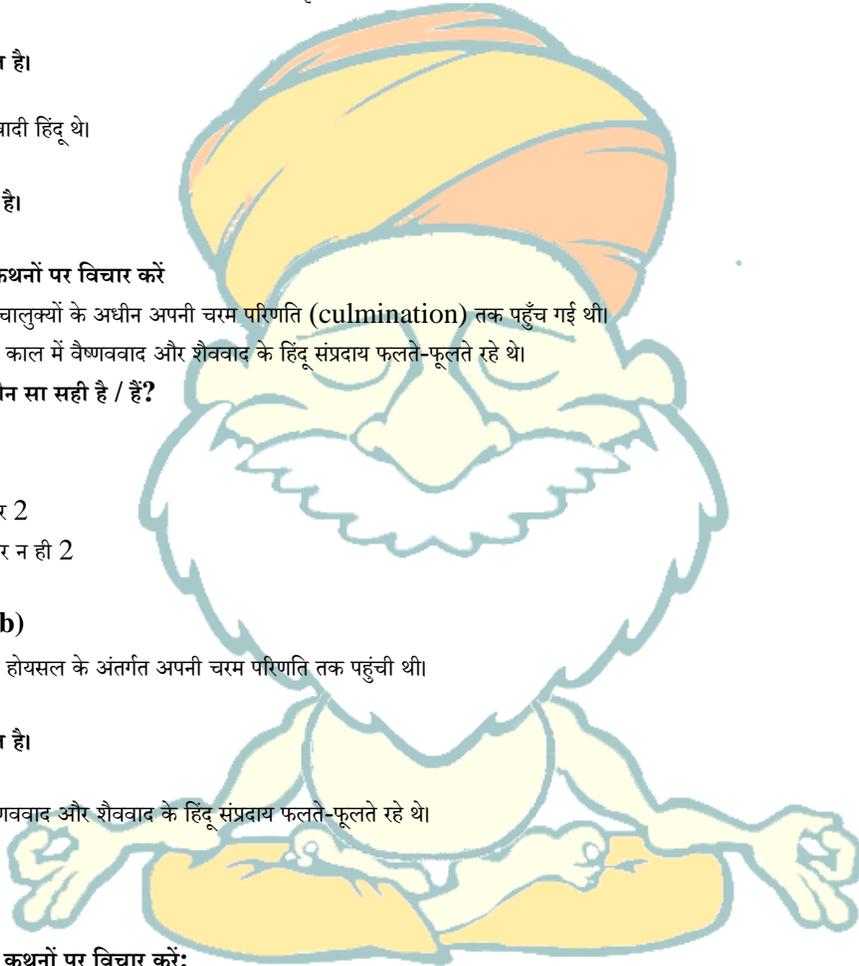
अतः कथन 2 सही है।

### Q.10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महेंद्र पंचम, राजेंद्र चोल प्रथम की शासन के दौरान श्रीलंका को फिर से हासिल करने में सफल रहा।
2. जयसिंहा द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य राजा) के विरुद्ध अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए राजेन्द्र चोल प्रथम द्वारा गंगाईकोंडचोलापुरम की स्थापना की गई थी।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

### Q.10) Solution (c)

श्रीलंका के राजा महिंद्र पंचम ने सिलोन (श्रीलंका) के उत्तरी भाग को चोलों से पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। राजेंद्र ने उसे हराया और दक्षिणी श्रीलंका को भी अधिग्रहित कर लिया। इस प्रकार पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था।

इसलिए कथन 1 गलत है।

गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना राजेन्द्र चोल प्रथम द्वारा की गई थी, जिन्होंने महिपाल प्रथम (पाल शासक) के खिलाफ अपनी विजय की स्मृति में स्थापना की थी।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.11) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सदन के नियमों में 'सचेतक' (whip) के कार्यालय का उल्लेख किया गया है।
2. 'विपक्ष के नेता' का कार्यालय संसदीय कानून में उल्लिखित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 11) Solution (a)

'सचेतक' (whip) का कार्यालय न तो भारत के संविधान में और न ही सदन के नियमों में और न ही संसदीय कानून में उल्लिखित है। यह संसदीय सरकार के कन्वेंशनों पर आधारित है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सदन के नेता और विपक्ष के नेता के कार्यालयों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, उनका उल्लेख क्रमशः सदन के नियमों और संसदीय कानून में किया गया है।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 12) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. स्थगन (adjournment) की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है जबकि अनिश्चित कालीन स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
2. किसी सदन के सत्रावसान और इसके नए सत्र के पुनर्गठन के बीच के काल को अवकाश (recess) कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 12) Solution (b)

स्थगन के साथ-साथ अनिश्चित कालीन स्थगन (adjournment sine die) की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

इसलिए कथन 1 गलत है।

किसी सदन के सत्रावसान और इसके नए सत्र के पुनर्गठन के बीच के काल को अवकाश (recess) कहा जाता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 13) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. एक बार सत्र का व्यवसाय पूरा हो जाने के बाद, पीठासीन अधिकारी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है।
2. सभी लंबित बिल, लोक सभा के सत्रावसान पर समाप्त (lapse) हो जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 13) Solution (b)**

एक बार सत्र का व्यवसाय पूरा हो जाने के बाद, राष्ट्रपति सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सत्रावसान बिल या सदन के समक्ष लंबित किसी अन्य व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि, सभी लंबित नोटिस सत्रावसान पर समाप्त हो जाते हैं और अगले सत्र में फिर से नोटिस जारी की जाती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. कोरम (Quorum) लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का दसवां (one-tenth) हिस्सा है, जबकि राज्यसभा के लिए यह पन्द्रहवां (one-fifteenth) है।
2. कोरम की गणना, पीठासीन अधिकारी को छोड़कर की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 14) Solution (c)**

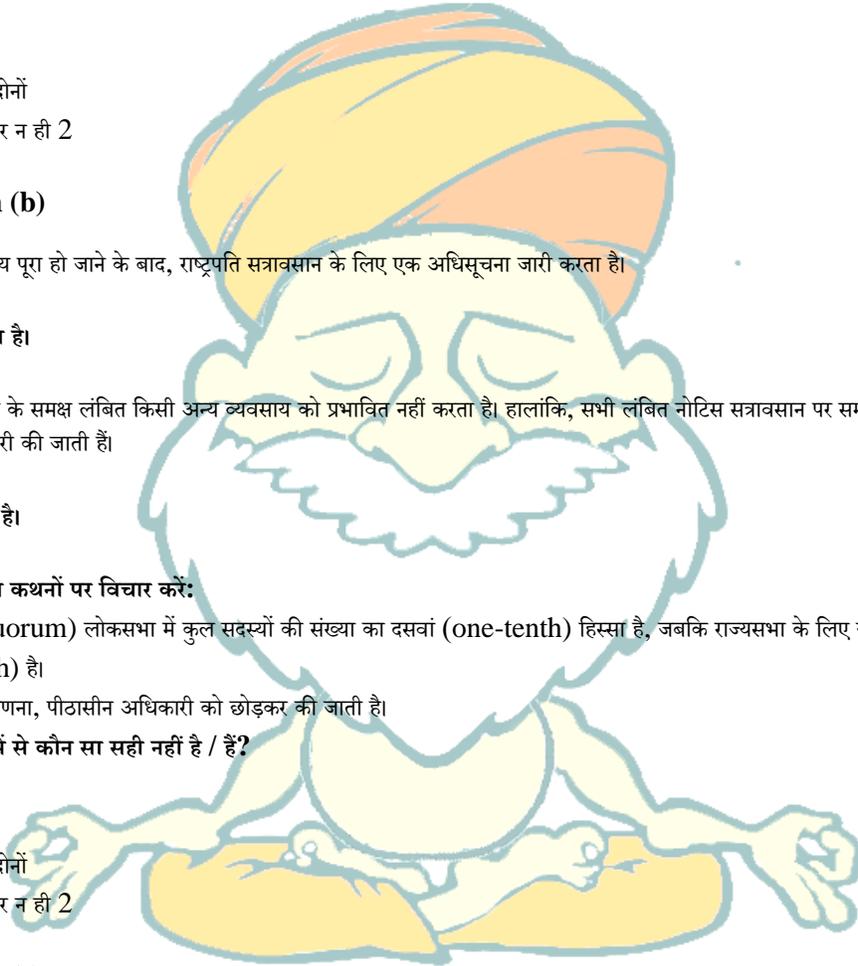
कोरम पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा होता है।

इसलिए कथन 1 और 2 गलत हैं।

**Q. 15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. संसद में अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है।
2. संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 15) Solution (c)

संसद में अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है तथा इसलिए पूरक प्रश्नों को पूछा जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 16) निम्नलिखित में से कौन संसदीय विशेषाधिकार के हकदार हैं?

- 1. महान्यायवादी
- 2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- 3. राष्ट्रपति
- 4. उप-राष्ट्रपति
- 5. केंद्रीय मंत्री

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1, 3 और 5
- b) केवल 1,2,3 और 5
- c) केवल 1 और 5
- d) 1, 2,3,4 और 5

### Q. 16) Solution (c)

संविधान ने राज्य विधायिका (या संसद) के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक विस्तारित किया है, जिन्हें राज्य विधायिका या उसकी किसी समिति की सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। इनमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री (केंद्रीय मंत्री) शामिल हैं।

राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल (राष्ट्रपति) तक विस्तारित नहीं हैं, जो राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है।

### Q. 17) 'अतिरिक्त अनुदान' (Excess grant) को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?

- a) व्यापार सलाहकार समिति
- b) आकलन समिति
- c) लोक लेखा समिति
- d) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

### Q. 17) Solution (c)

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए अनुमोदित राशि से अधिक धन खर्च किया गया हो तो अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। इसपर वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है।

मतदान के लिए लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

**Q. 18) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही विनियोग अधिनियम बनता है।
2. सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की आकस्मिकता निधि से धन नहीं निकाल सकती है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?**

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 18) Solution (a)**

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है।

संविधान कहता है कि 'कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत के समेकित कोष से कोई धन नहीं निकाला जाएगा'।

**Q. 19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समितियों (Consultative committees) का गठन किया जाता है।
2. परामर्शदात्री समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।

**उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?**

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 19) Solution (c)**

संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाता है।

**इसलिए कथन 1 सही है।**

परामर्शदात्री समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। परामर्शदात्री समितियाँ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से संबद्ध होती हैं।

**इसलिए कथन 2 सही है।**

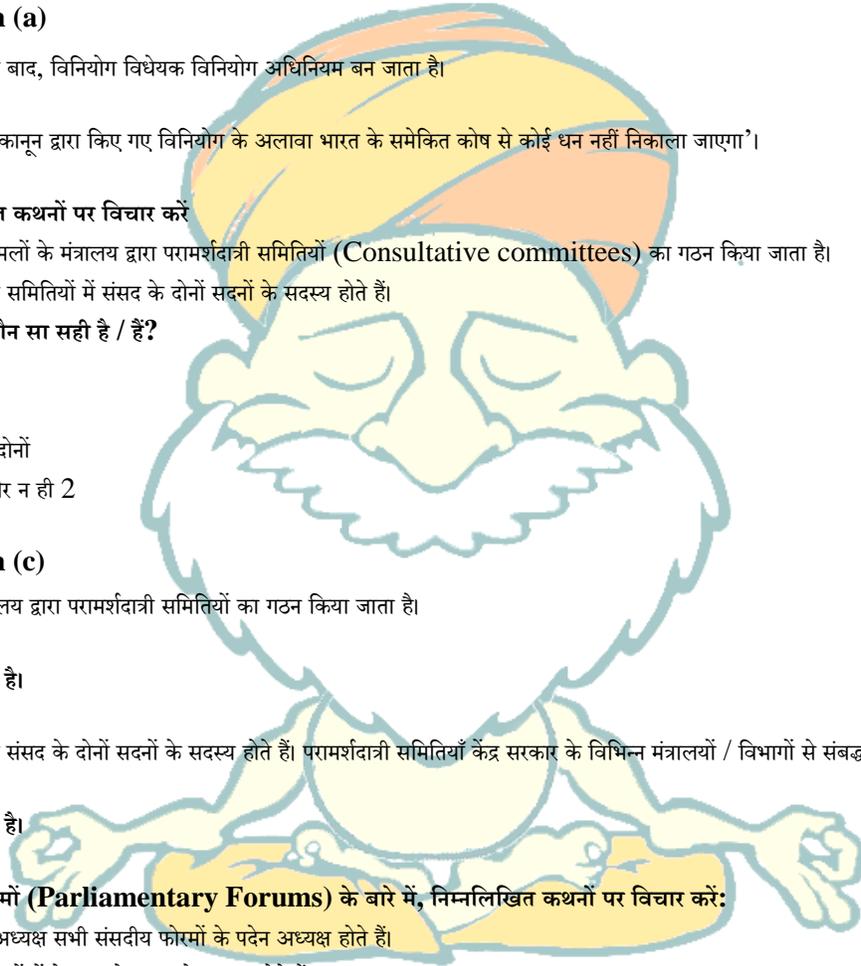
**Q.20) संसदीय फोरमों (Parliamentary Forums) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय फोरमों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
2. संसदीय फोरमों में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं।

**उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?**

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 20) Solution (c)**



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

लोक सभा अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसमें राज्य सभा के सभापति पदेन अध्यक्ष होता है, संसदीय फोरम को छोड़कर सभी फोरमों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

प्रत्येक संसदीय फोरम में 31 से अधिक सदस्य (राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति को छोड़कर) शामिल होते हैं, जिनमें से अधिकतम 21 लोकसभा से होते हैं और अधिकतम 10 राज्यसभा से होते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 21) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करती है।
2. संविधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए तभी योग्य माना जाता है, जब वह राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 21) Solution (c)**

भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडाई मॉडल पर आधारित है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संविधान में केवल दो योग्यताएँ हैं:

कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. राज्यपाल को पद की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
2. संविधान कोई आधार वर्णित नहीं करता है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 22) Solution (b)**

राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में, उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

इसलिए कथन 1 गलत है।

संविधान कोई आधार वर्णित नहीं करता है जिस पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. राज्य के महाधिवक्ता को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जैसा राज्यपाल निर्धारित कर सकता है।
2. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 23) Solution (a)**

राज्यपाल एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। राज्यपाल के प्रसादपर्यंत महाधिवक्ता पद पर बना रहता है।

इसलिए कथन 1 सही है।

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति (discretionary power) है।
2. राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, यदि ऐसा मृत्युदंड राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 24) Solution (c)**

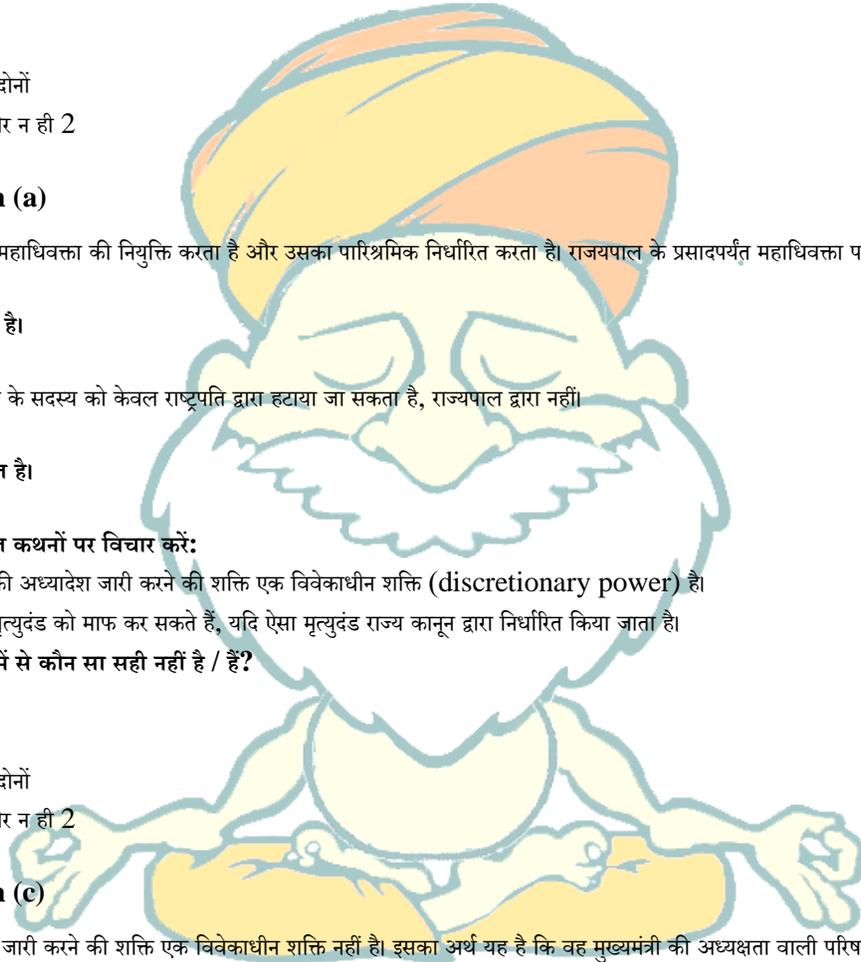
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है या वापस ले सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि किसी राज्य कानून के आधार पर मृत्युदंड दिया जाता है, तब भी क्षमा प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

1. संविधान के अनुसार आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पहले उसे विधान सभा में बहुमत साबित करना होगा।
2. उप-राज्यपाल (Lieutenant Governor) भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र पदनाम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 25) Solution (d)

संविधान के अनुसार आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पहले उसे विधान सभा में बहुमत साबित करना होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति एक व्यवस्थापक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है; यह उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। वर्तमान में, यह दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मामले में उपराज्यपाल है तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के मामले में प्रशासक है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 26) निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है?

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. तेलंगाना
4. ओडिशा
5. कर्नाटक

सही कूट का चयन करें:

- a) केवल 1, 3 और 5
- b) केवल 1, 2, 3 और 5
- c) केवल 1 और 5
- d) 1, 2, 3, 4 और 5

### Q. 26) Solution (b)

भारत में छह राज्यों में विधान परिषदें हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

### Q. 27) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीन सूचियों (केंद्र, राज्य, समवर्ती) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
2. संसद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 27) Solution (a)

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संसद तीन सूचियों (राज्य सूची सहित) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

**Q. 28) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है जो एक राज्यपाल की तरह राज्य के प्रमुख के समान होता है।
2. राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आसन्न केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 28) Solution (b)**

प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है तथा राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 29) भारतीय संदर्भ में, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार (Constitutional discretion) है?**

1. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश
2. एक आसन्न केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए।
3. राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक का आरक्षण (Reservation)।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

**Q. 29) Solution (d)**

राज्यपाल के पास निम्नलिखित मामलों में संवैधानिक विवेकाधिकार है:

1. राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक का आरक्षण।
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।
3. आसन्न केंद्रशासित प्रदेश (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए।
4. एक स्वायत्त आदिवासी जिला परिषद को खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार द्वारा देय राशि का निर्धारण करना।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

5. राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना।

**Q.30) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. संसद द्वारा विधान परिषदों का निर्माण अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
2. विधान परिषदों के निर्माण के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 30) Solution (b)**

संसद एक विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या इसका सृजन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधान सभा उस प्रस्ताव का प्रस्ताव पारित करती है।

इस तरह के एक विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात् विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत तथा विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत।

संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान के संशोधन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए तथा इसे कानून के एक साधारण भाग की तरह पारित किया जाता है (अर्थात्, साधारण बहुमत द्वारा)।

इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है।

**Q. 31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
2. संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी मामले में चालीस से कम नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 31) Solution (d)**

प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

इसलिए कथन 1 सही है।

संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी मामले में चालीस से कम नहीं होगी।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 32) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. एक व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक वह पैंतीस साल का नहीं हो जाता।
2. संविधान किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

### Q. 32) Solution (d)

कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक वह तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 33) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- विधान सभा के अध्यक्ष, विधान सभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं।
- विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

### Q. 33) Solution (a)

विधान सभा के अध्यक्ष विधान सभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 188:

विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी सदस्यता लेगा, तथा तीसरी अनुसूची के तहत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण या पुष्टि करेगा।

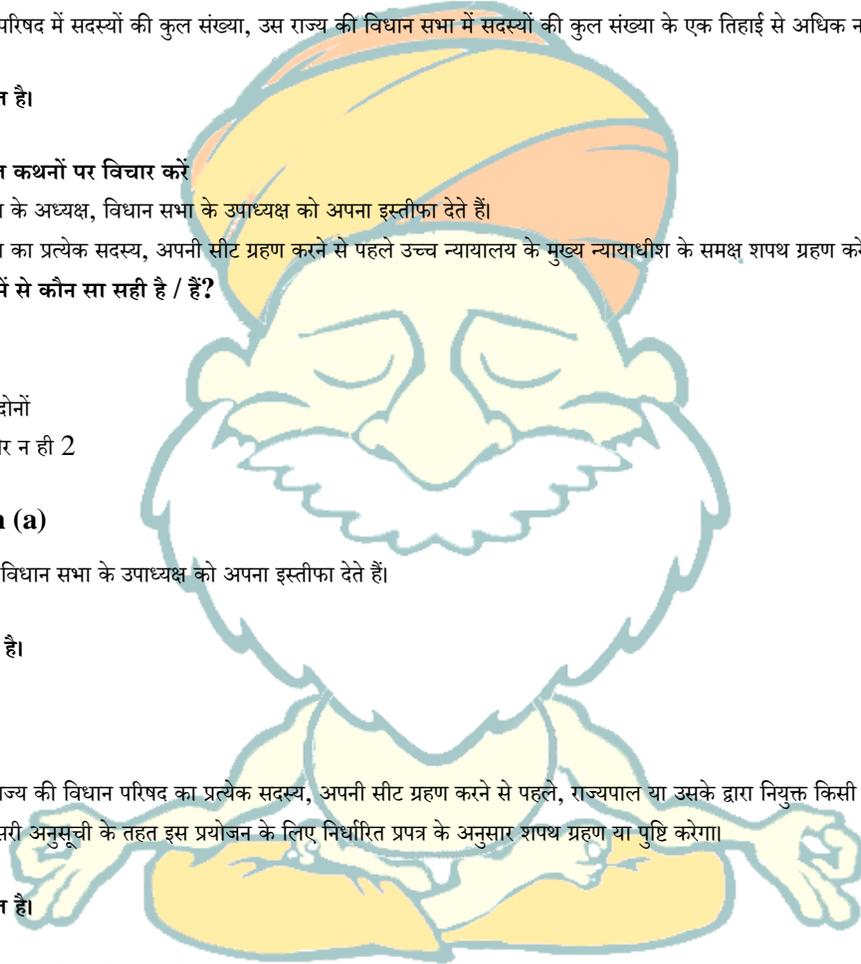
इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 34) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- राज्य विधान परिषद की बैठकें आयोजित करने के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है।
- यदि किसी भी समय राज्य विधान सभा की बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन का सत्रावसान (prorogues) कर देते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

### Q. 34) Solution (c)

किसी राज्य के विधानमंडल/ परिषद की बैठक का गठन करने के लिए न्यूनतम कोरम आवश्यक है, जो सदन के कुल सदस्यों का दसवां भाग होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

यदि किसी भी समय राज्य विधान सभा की बैठक के दौरान कोई कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष सदन को स्थगित (adjourn) कर देते हैं या बैठक को रोक (suspend) देते हैं जब तक कि कोरम पूर्ण न हो।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के रूप में चुना जाता है, (राष्ट्रपति द्वारा नियमों में निर्दिष्ट निश्चित अवधि की समाप्ति पर), तो उसके गृह राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के विधानसभाओं में व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी।
2. अध्यक्ष राज्य विधान सभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को अवश्य स्वीकार करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 35) Solution (d)

अनुच्छेद 190 (2): कोई भी व्यक्ति पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होगा तथा यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधानसभाओं का सदस्य चुना जाता है, तो इस तरह राष्ट्रपति द्वारा नियमों में निर्दिष्ट निश्चित अवधि की समाप्ति पर, ऐसे में सभी राज्यों के विधानसभाओं में उस व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी, जब तक उसने एक विधानसभा में अपनी सीट को छोड़कर अन्य सभी से इस्तीफा नहीं दिया हो।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राज्य विधान सभा के सदस्य के किसी भी इस्तीफे के मामले में, यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा या ऐसी पूछताछ करने के बाद, जैसा कि वह उचित समझता है, अध्यक्ष या चेरमैन, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि ऐसा इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, वह इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 36) राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक की विधायी प्रक्रिया के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- a) जब एक विधेयक, जो परिषद में उत्पन्न हुआ है और विधानसभा में भेजा गया था, विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है और मृत हो जाता है।
- b) विधेयक को किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- c) संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था का प्रावधान करता है ताकि दोनों सदनों के बीच असहमति का समाधान हो सके।
- d) विधान सभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद को ओवरराइड कर सकती है, लेकिन विधान परिषद ऐसा नहीं कर सकती है।

### Q. 36) Solution (c)

संविधान, दोनों सदनों के बीच एक विधेयक पर असहमति के समाधान के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए तंत्र का प्रावधान प्रदान नहीं करता है। दूसरी ओर, साधारण विधेयक पर दोनों के बीच असहमति को सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।

### Q. 37) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

1. दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
2. जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक रखता है, तो विधेयक की स्वीकृति में राज्यपाल की आगे कोई भूमिका नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 37) Solution (b)

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न विधान परिषद के मामले में, चेयरमैन तथा विधानसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ एक विधेयक रखता है:

यदि विधेयक सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है और फिर से पारित हो जाता है, तो विधेयक को पुनः केवल राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है, तो यह एक अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 38) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाएं।
2. किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य, कानून द्वारा राज्य विधायिका द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 38) Solution (b)

विधान सभा और राज्य के विधान परिषद के सदस्य कानून द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

इसलिए कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।

### Q. 39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक धन विधेयक राज्य विधायिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. जब राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक (राज्यपाल द्वारा) आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकते।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

### Q. 39) Solution (d)

धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस नहीं कर सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.40) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान (prorogation) के कारण समाप्त (lapse) नहीं होगा।
2. राज्य विधान परिषद में लंबित एक विधेयक, जो विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त (lapse) नहीं होगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 40) Solution (d)

राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

राज्य विधान परिषद में लंबित एक विधेयक, जो विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद के पास, जब आपातकाल की उद्घोषणा संचलन में हो, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।
2. राष्ट्रपति, संसद की सहमति से, किसी भी मामले के संबंध में एक राज्य सरकार को कुछ कार्य सौंप सकता है, जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 41) Solution (b)

संसद के पास, जब आपातकाल की उद्घोषणा संचलन में हो, राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

इसलिए कथन 1 सही है।

राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से किसी भी विषय के संबंध में सरकार या उसके अधिकारियों को सशर्त या बिना शर्त कार्य सौंप सकते हैं, जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 42) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. किसी केंद्रशासित प्रदेश (राज्य शामिल नहीं हैं) के मामले में, संसद के पास राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है।
2. संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 42) Solution (c)**

संसद के पास भारत के केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, इस बात के बावजूद कि इस मामले को राज्य सूची में शामिल किया गया है।

इसलिए कथन 1 सही है।

संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी कर को लागू करने वाले किसी भी कानून को बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है। (संसद के पास अवशिष्ट कर लगाने की विशेष शक्तियां हैं)

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. भारत सरकार ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित न्यायिक कार्यों के लिए किसी भी क्षेत्र की सरकार (भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना) के साथ समझौता कर सकती है।
2. मिजोरम के राज्यपाल भी निर्देश जारी कर कह सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य के एक आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।

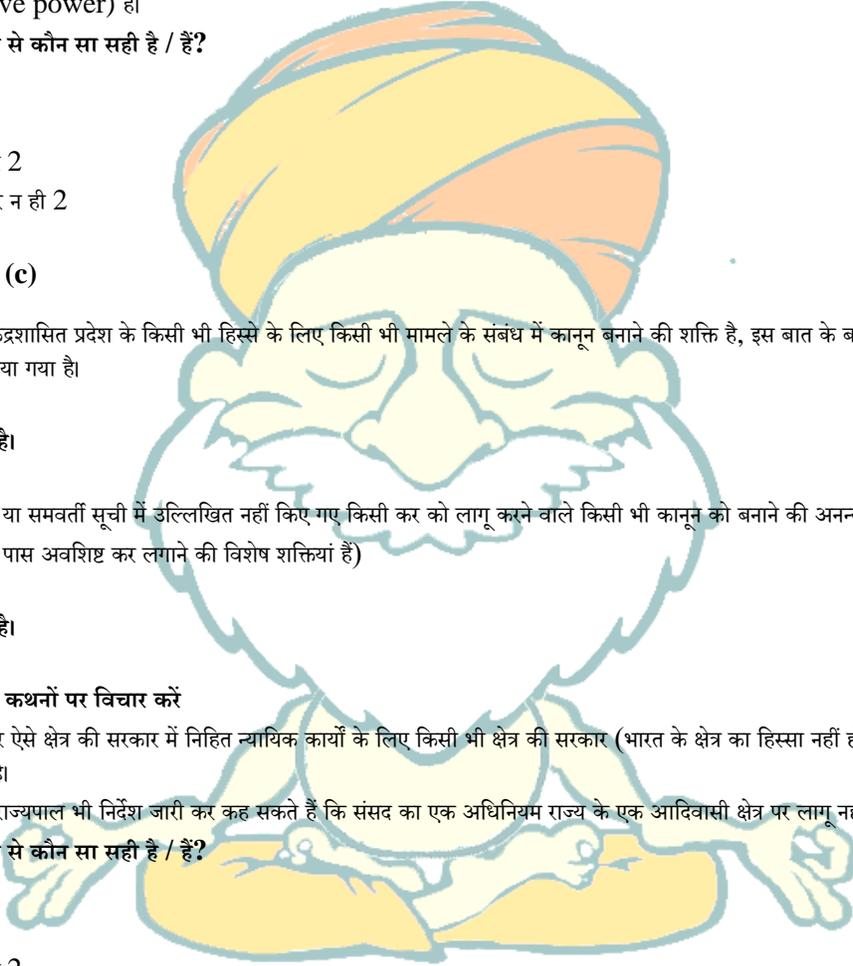
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 43) Solution (a)**

भारत सरकार ऐसे क्षेत्र की सरकार में निहित किसी भी कार्यकारी, विधायी या न्यायिक कार्यों को करने के लिए भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होने के साथ किसी भी क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता कर सकती है। लेकिन ऐसा समझौता लागू होते समय किसी कानून के अधीन प्रशासित होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

असम के राज्यपाल निर्देश जारी कर यह कह सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य में एक आदिवासी क्षेत्र (स्वायत्त जिले) पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों) के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 44) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करने की शक्ति है।
2. संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 44) Solution (a)**

संसद कानून द्वारा संघ सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में संसद या किसी भी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए कानून प्रदान कर सकती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति (exclusive power) है।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 45) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. संसद द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर अमान्य माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन (extra-territorial operation) होगा।
2. केवल संसद वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बना सकती है, जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति होती है।

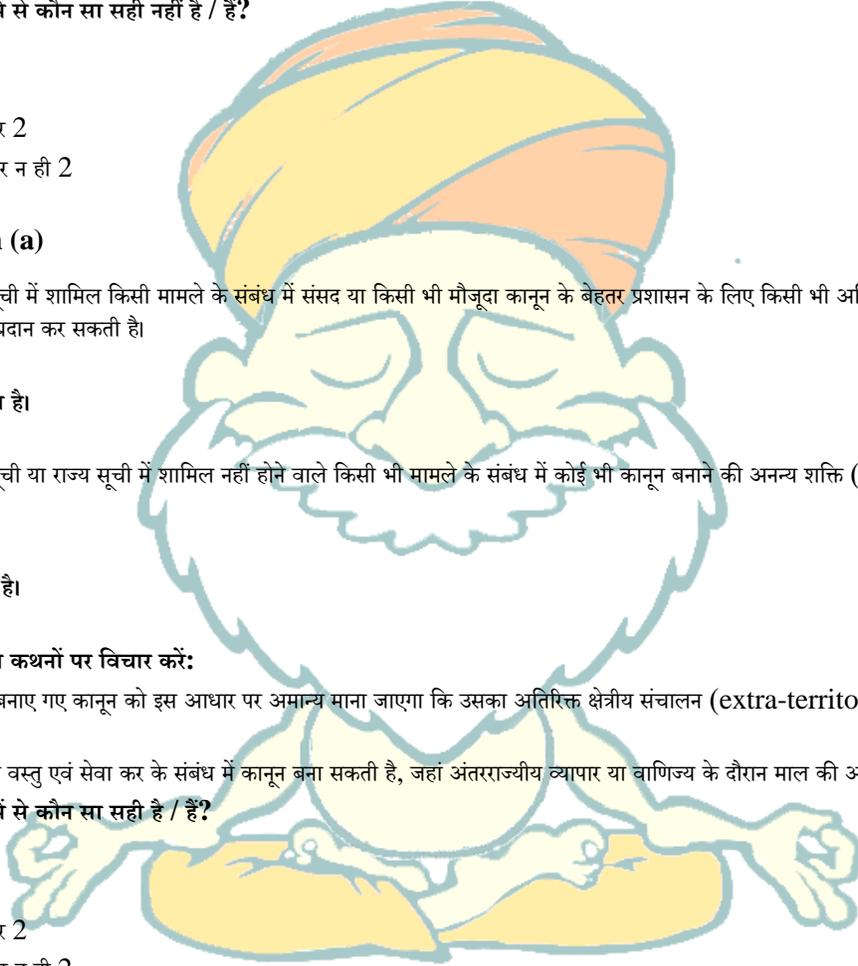
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 45) Solution (b)**

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन (extra-territorial operation) होगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

संसद के पास वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जहां माल, या सेवाओं की आपूर्ति, या दोनों अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 46) संविधान की 5 वीं अनुसूची के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. राज्यपाल को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र (scheduled area) घोषित करने का अधिकार है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है।
3. जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श के बाद राज्यपाल को एक अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बनाने का अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

**Q. 46) Solution (c)**

किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। वह इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसकी सीमा रेखा को परिवर्तित कर सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के बारे में सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है। इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से तीन-चौथाई राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। वह जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद एक अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम भी बना सकते हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

**Q. 47) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रबल (prevails) होता है।
2. शिक्षा आरंभ में राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय थी, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय सूची में लाया गया।
3. एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 3
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

**Q. 47) Solution (c)**

समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच संघर्ष के मामले में, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रबल होता है।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

इसलिए कथन 1 सही है।

42 वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया।

इसलिए कथन 2 गलत है।

एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।

इसलिए कथन 3 गलत है।

**Q. 48) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, प्रत्येक राज्य को नहीं।
2. अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान नीति आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को दिया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 48) Solution (a)**

सांविधिक अनुदान (Statutory Grants): अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, प्रत्येक राज्य को नहीं। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि तय की जा सकती है। ये राशि हर साल भारत के समेकित कोष पर भारित होती है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत सांविधिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 49) केंद्र को निम्नलिखित में से किस मामले में अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है?**

1. राज्य द्वारा संचार के साधनों का निर्माण और रखरखाव।
2. राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय।
3. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का खाका और क्रियान्वयन।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- a) केवल 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

**Q. 49) Solution (d)**

राज्य द्वारा संचार के साधनों (राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के) का निर्माण और रखरखाव;

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय;

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का खाका और क्रियान्वयन।

**Q.50) निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं (Federal features) माना जाता है?**

1. लिखित संविधान
2. एकीकृत न्यायपालिका
3. शक्तियों का विभाजन
4. एकल संविधान
5. एकीकृत चुनावी मशीनरी

**सही कूट का चयन करें:**

- a) केवल 1, 2, 4 और 5
- b) केवल 1, 2, 3 और 5
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2, 3, 4 और 5

**Q. 50) Solution (c)**

दोहरी राज्यव्यवस्था (Dual Polity), लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की कुछ संघीय विशेषताएं हैं।

एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान, एकीकृत चुनाव मशीनरी, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की कुछ एकल/ केंद्रीय विशेषताएं हैं।

**Q. 51) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तीस होगी।
2. चौथे न्यायाधीशों के मामले (Fourth Judges Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर गठित कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?**

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

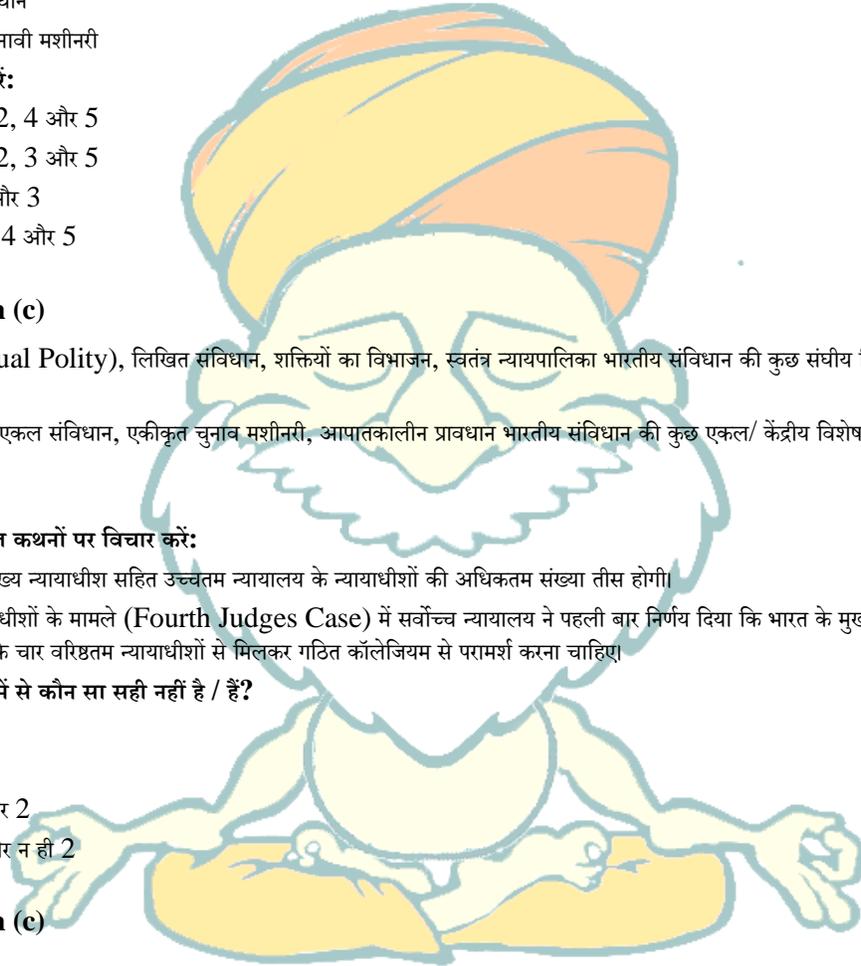
**Q. 51) Solution (c)**

भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तैतीस (33) होगी।

**इसलिए कथन 1 गलत है।**

तीसरे न्यायाधीशों के मामले (Third Judges Case) में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार निर्णय सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोलेजियम से परामर्श करना चाहिए जिसमें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। (दूसरे न्यायाधीशों के मामले (second judges case) में यह केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीश था)

**इसलिए कथन 2 गलत है।**



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

**Q. 52) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. 84 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 52) Solution (d)**

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति की निश्चित प्रक्रिया पर संविधान मौन है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नियुक्त करना एक कन्वेंशन है जिसे 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण कर सकता है जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 53) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है, भारत के भीतर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, वह किसी भी न्यायालय में कोई पदभार ग्रहण नहीं करेगा।
2. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन सर्वोच्च न्यायालय के अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 53) Solution (d)**

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में पदभार ग्रहण नहीं करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन किसी अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति न्यायालय में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q. 54) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

1. जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो राष्ट्रपति एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित करता है।
2. राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 54) Solution (a)

जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही ऐसा कर सकता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 55) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान यह कहता है कि कानून द्वारा संसद (राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ) अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में नियुक्त कर सकती है।
2. भारतीय क्षेत्र में, आपराधिक मामलों के केस में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन सिविल मामलों में नहीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 55) Solution (d)

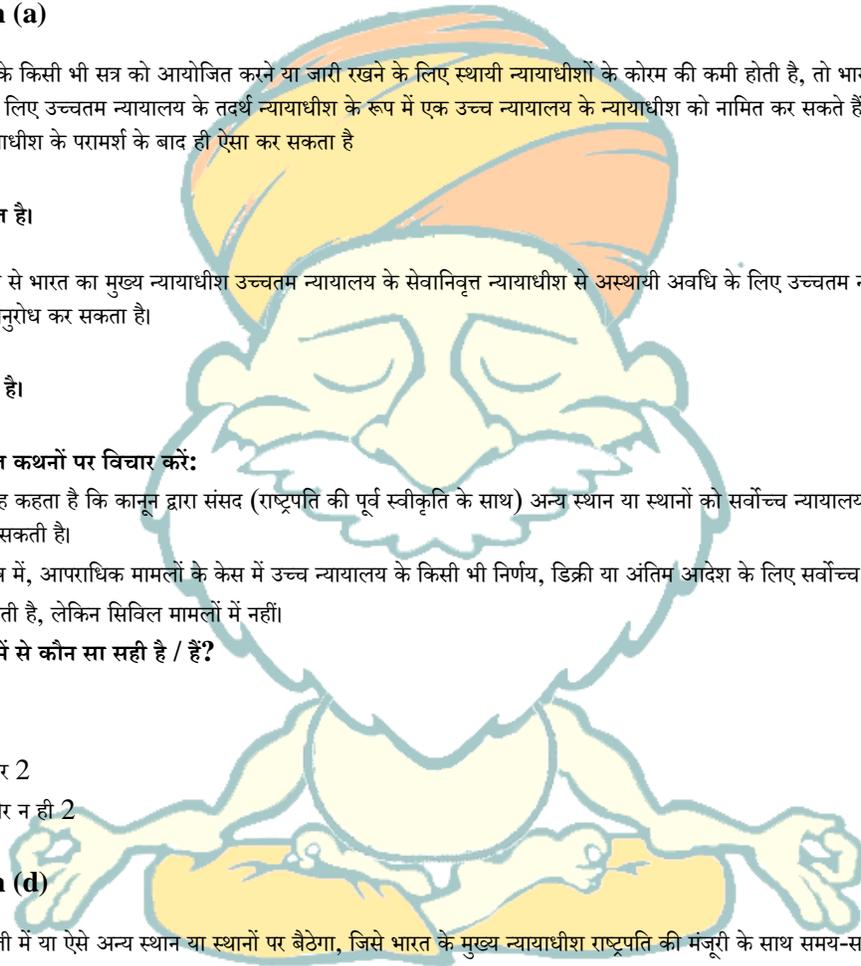
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ समय-समय पर नियुक्ति कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भारतीय क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, चाहे वह एक नागरिक, अपराधी या अन्य कार्यवाही में हो, के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 56) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:



## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं की जाती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति (overriding power) के अधीन हो जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 56) Solution (c)

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

किसी राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, यह संसद की अतिव्यापी शक्ति के अधीन हो जाती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण निलंबित होता है, हालांकि राज्य विधानसभाएं निलंबित नहीं होती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 57) अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?**

- a) अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।
- b) अनुच्छेद 358 आपातकाल घोषित होते ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है।
- c) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल समाप्ति के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- d) अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है।

### Q. 57) Solution (b)

अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन (अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर) से संबंधित है।

इसलिए कथन 1 सही है।

आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 358 स्वचालित रूप से अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 359 किसी भी मौलिक अधिकार को स्वचालित रूप से निलंबित नहीं करता है। यह केवल राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

आपातकाल के समाप्त होने के बाद भी, आपातकाल के दौरान की गयी कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल के दौरान की गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

इसलिए कथन 3 सही है।

अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामले में संचालित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

इसलिए कथन 4 सही है।

**Q. 58) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 58) Solution (c)**

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके, संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है।

**Q. 59) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) में ही रिट जारी कर सकता है।
2. अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य (exclusive) नहीं है लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती (concurrent) है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 59) Solution (c)**

उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर, बल्कि अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी रिट जारी कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण उसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के साथ अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती है। इसका अर्थ है कि, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q.60) निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करता है?**

1. भारत के राष्ट्रपति संसद के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं।
3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के समेकित कोष पर भारित किया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता है।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:

- केवल 1
- केवल 1 और 2
- केवल 3
- 1, 2 और 3

### Q. 60) Solution (c)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल संविधान में वर्णित उस तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर आसीन नहीं रहते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के समेकित कोष पर भारित किया गया है। इस प्रकार, वे संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं।

इसलिए कथन 3 सही है।

### Q. 61) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- संघीय न्यायालय (Federal Court) शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के पास सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) देने का विवेकाधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

### Q. 61) Solution (b)

अनुच्छेद 135 में संघीय न्यायालय (Federal Court) शब्द का उल्लेख है।

इसलिए कथन 1 सही है।

अनुच्छेद 136 (1): उच्चतम न्यायालय, अपने विवेकाधिकार से, किसी भी कारण या मामले को पारित करने या भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय, डिक्री, दुरु संकल्प, वाक्य या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) दे सकता है।

खंड (1) में कुछ भी सशस्त्र बलों से संबंधित या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या लागू किए गए किसी भी निर्णय पर लागू नहीं होगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 62) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

1. सर्वोच्च न्यायालय दोनों उच्च न्यायालयों की पूर्व सहमति के साथ ही किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 62) Solution (b)

सर्वोच्च न्यायालय, यदि न्याय की प्राप्ति के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

उच्च न्यायालय की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

अनुच्छेद 141: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 63) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 143 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी गई राय उनके लिए बाध्यकारी है।
2. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से आम तौर पर न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 63) Solution (b)

अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी होती है, न्यायिक घोषणा नहीं। इसलिए, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, आमतौर पर न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 64) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तीन होगी।
2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

### Q. 64) Solution (a)

न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होंगी, जो किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है, जिसमें कानून का एक बड़ा प्रश्न होता है, जो इस संविधान की व्याख्या के अनुसार है या अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य के लिए है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों या कुछ अन्य न्यायाधीशों या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिकृत न्यायालय के अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 65) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- उच्च न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है।
- यदि कोई प्रश्न किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित आता है, तो यह प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

### Q. 65) Solution (a)

प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख-न्यायालय (court of record) होगा और इस तरह के न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होगी।

इसलिए कथन 1 सही है।

यदि कोई प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु से संबंधित होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न का निर्णय लिया जाएगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 66) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- कोई भी व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला हो, वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं करेगा।
- जब एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो कार्यालय के कर्तव्यों को न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसे राज्यपाल इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 66) Solution (d)

कोई भी व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद, एक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया हो, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय में या भारत में किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा।

इसलिए कथन 1 गलत है।

जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तो अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने पर, कार्यालय के कर्तव्यों को ऐसे किसी एक के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। राष्ट्रपति न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q. 67) संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन को कम कर सकते हैं।
2. केंद्र यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए आरक्षित होंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 67) Solution (a)

वित्तीय आपातकाल के मामले में, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन को कम कर सकते हैं।

इसलिए कथन 1 गलत है।

केंद्र यह निर्देश दे सकता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए आरक्षित होंगे।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q. 68) राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल संचलन में रहता है, राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यदि संसद सत्र में नहीं होती है।
2. राष्ट्रपति या तो केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं और राष्ट्रपति के ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q. 68) Solution (d)

# IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संचलन में हो, राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यदि संसद सत्र में नहीं हो।

इसलिए कथन 1 सही है।

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संचलन में हो, राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

इसलिए कथन 2 सही है।

**Q. 69) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यदि उच्च न्यायालय के कार्य (business) में अस्थायी वृद्धि होती है, तो राष्ट्रपति एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
2. उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q. 69) Solution (c)**

यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य (business) में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसके कार्य के शेष बचे रहने के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या उस समय बढ़नी चाहिए, तो विधिवत योग्य व्यक्ति को इस अवधि के लिए न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकता है, इसकी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रहेगा।

इसलिए कथन 2 गलत है।

**Q.70) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) है जबकि विवाह, तलाक से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है।
2. सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है तथा निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q.70) Solution (b)**

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों में है, जबकि उच्च न्यायालय का विवाह, तलाक, वसीयत, संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद आदि मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है।

इसलिए कथन 1 गलत है।

## IASbaba's Integrated Revision Plan (IRP) 2020 Week-5

---

सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है तथा निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।

इसलिए कथन 2 सही है।

